सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए
संपर्क करे
9303289950
7987166110

वर्ष- 17 अंक - 306 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 20 अगस्त 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

कांग्रेस ने वीर भूमि पर दी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा और कई अन्य पार्टी नेताओं ने बृहस्पतिवार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 'वीर भूमि' पहुंचकर राजीव गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। खरगे ने राजीव गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने लाखों लोगों में उम्मीद दी और भारत को 21वीं सदी की संभावनाओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

डॉक्टरों को मिलेगी यूआईडी कहीं भी कर सकेंगे प्रैक्टिस

नई दिल्ली। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर रजिस्टर्ड डॉक्टर को केंद्रीय स्तर पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईडी) देने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत एक बार राज्य मेडिकल रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर को देश के किसी दूसरे राज्य में प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। यह प्रस्ताव डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस लाइसेंस से जुड़े 2026 के ड्राफ्ट नियमों में रखा गया है। इसके मुताबिक, राज्य मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद एनएमसी का एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड डॉक्टर को यूआईडी जारी करेगा। यह नंबर डॉक्टर को नेशनल मेडिकल रजिस्टर (एनएमआर) में रजिस्टर्ड करेगा और उन्हें देशभर में प्रैक्टिस करने की अनुमति देगा।

भारत ने अफगानिस्तान को भेजे कई कंटेनर दवाई, कहा ये

नई दिल्ली। भारत ने अपने पड़ोसी दोस्त अफगानिस्तान को दवाओं की बड़ी-बड़ी खेप भेजी है। ये खेप बड़े-बड़े कंटेनरों में भेजी गई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। भारत अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों में अकसर मदद भेजता रहा है। तालिबान शासित अफगानिस्तान को भेजे गए दवा कंटेनरों को देखकर पाकिस्तान तिलमिलाकर रह जाएगा, जिसके साथ आए दिन सीमा पर संघर्ष करना पड़ रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर फोटो भी पोस्ट की हैं। उन्होंने लिखा-अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाना। अफगानिस्तान के मित्रवत लोगों के साथ अपनी मजबूत स्वास्थ्य साझेदारी को दोहराते हुए, एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां भेजीं।

पिलग्रिम के साथ ही इको-टूरिज्म मैप पर तेजी से उभरेगा मांदागिरी पर स्थित मुचुकुंद ऋषि आश्रम

श्रीकंचनपथ समाचार

धमतरी। जिले के नगरी (सिहावा) में मांदागिरी पर्वत पर स्थित मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली अब नया पर्यटन केंद्र बनेगा। मेचका गांव के पास मेखलाकार पहाड़ी पर स्थित पौराणिक मुचुकुंद ऋषि की यह पावन तपोस्थली श्रद्धालुओं की आस्था के साथ ही पर्यटकों को बेहद आकर्षित कर रही है।

प्राकृतिक और आध्यात्मिक विरासत में मांदागिरी पर्वत का विशेष महत्व है। मेखलाकार पहाड़ी पर मौजूद मुचुकुंद ऋषि की तपोस्थली श्रद्धा, अध्यात्म और प्रकृति के अद्भुत संगम के रूप में जानी जाती है। धमतरी कलेक्टर ने बताया कि यहां की आध्यात्मिक और प्राकृतिक क्षमता को देखते हुए योजना बनाई जा रही है। यह स्थल राज्य के प्रमुख इको-टूरिज्म और पिलग्रिम टूरिज्म मैप पर तेजी से उभरेगा।

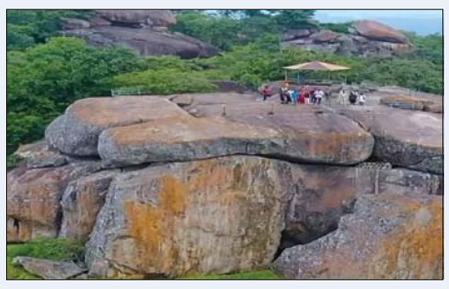

मांदागिरी की खूबियां

तालाब, प्राचीन प्रतिमाएं और माता सीता सहित देवी-देवताओं के मंदिर हैं। पहाड़ी से सोंढूर डैम और वन दिखाई देते हैं, जो ट्रेकिंग के लिए उत्तम है।

मुचुकंद आश्रम

मुचुकुंद महाराज इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता के पुत्र थे। उनकी तपोभूमि 'सप्तऋषि तपोभूमि' की आध्यात्मिक विरासत को समृद्ध करता है।

ट्रेकिंग और एडवेंचर

स्थल को धार्मिक आस्था के साथ ही ट्रेकिंग और एडवेंचर स्पॉट्स के रूप में भी विकसित किया जायेगा। इससे रोजगार के अवसर बनेंगे।

पाकिस्तान की हरकत का भारत ने दिया जवाब

दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर चला बुलडोजर, बैरिकेड-फेंसिंग हटाई गई

नई दिल्ली (ए.)। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बने अवैध ढांचों को बुधवार देर रात बुलडोजर से हटा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, ये ढांचे हाई कमीशन की तय सीमा से बाहर बने थे। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब दो दिन पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड और पार्किंग पोल हटाए गए थे।

पाकिस्तान हाई कमीशन का ऑफिस दिल्ली के चाणक्यपुरी के शांतिपथ पर है। यहां बैरिकेड, फेंसिंग और वीजा सेक्शन के पास कतार प्रबंधन के लिए बनाए गए ढांचे भी हटाए गए। हालांकि पाकिस्तान हाई कमीशन की मेन बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

संबंधित एजेंसियों ने जेसीबी की मदद से हाई कमीशन के बाहर कार्रवाई की। मौके से ली गई तस्वीरों में टूटी रेलिंग, गेट, लोहे के फ्रेम, छत की चादरें, ईंट और कंक्रीट के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। बाहरी हिस्से की सफेद मेटल फेंसिंग और कुछ कॉरुगेटेड रूफिंग भी हटा दी गई।

बुलडोजर एक्शन हाई कमीशन की मेन बिल्डिंग तक नहीं हुआ। मेन गेट, सफेद दीवारें और पाकिस्तानी निशान वाला बड़ा प्रवेश द्वार सुरक्षित रहा। परिसर के कुछ हिस्सों में कांटेदार तार भी लगे दिखाई दिए।

तोड़फोड़ के बाद वीजा सेक्शन के सर्विस काउंटर दिखाई दे रहे थे। वहां 'विंडो 1', 'पाकिस्तान पासपोर्ट ऑनली' और 'विंडो-5 / कलेक्शन ऑफ वीजा एप्लीकेंट्स' जैसे बोर्ड लगे थे। काउंटरों के आसपास टूटी फेंसिंग और कंस्ट्रक्शन सामान पड़े थे।

कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत की टिप्पणी से पड़ोसी नाराज

दोनों देशों के बीच अमेरिकी राजदूत की कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर भी तनाव बढ़ा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर दौरे के दौरान 19 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्षेत्र के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है।

56 नए जजों को मिली पदस्थापना कईयों का तबादला, नई पोस्टिंग भी

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव द्वारा 56 नए सिविल जजों (जूनियर डिवीजन) को पहली पदस्थापना दी गई है। इसके साथ ही हायर ज्यूडिशियल सर्विस और लोअर ज्यूडिशियल सर्विस के कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई पोस्टिंग आदेश जारी किए गए। नव-नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को 29 अगस्त तक कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

हायर ज्यूडिशियल सर्विस के 5 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें दंतेवाड़ा परिवार न्यायालय के जज हरीश कुमार अवस्थी को प्रथम एडीजे, रायपुर, ममता पटेल को अंबिकापुर से द्वितीय एडीजे, बिलासपुर, ज्योति अग्रवाल को पेंड्रारोड से न्यायाधीश, राजनांदगांव पदस्थ किया गया है। नमिता मिंज भास्कर को धमतरी और एन सिंह साहू को राजनांदगांव से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है।

रायपुर के प्रथम एडीजे नीरज शर्मा को रायपुर की विशेष अदालत (एससीएसटी) का स्पेशल जज नियुक्त किया गया है। वहीं अंबिकापुर में कमलेश जगदल्ला को एडीजे और स्मिता रत्नावत को एडीजे (पोक्सो) की जिम्मेदारी दी गई है। सतीश कुमार खाखा को प्रतापपुर से सीजेएम एवं प्रथम सिविल जज सीनियर डिवीजन, मुंगेली पदस्थ किया गया है। भगवान दास पनिका को प्रतापपुर, श्वेता पटेल को छुईखदान, ईशान व्यास को दुर्ग और नीलेश जगदल्ला को राजनांदगांव पदस्थ किया गया है। दुर्ग के द्वितीय अतिरिक्त जज रवि कुमार कश्यप को प्रतिनियुक्ति पर हाईकोर्ट में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किया गया है।

ग्राहम स्टेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली (ए.)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ओडिशा सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में सजायाफ्ता रवींद्र पाल उर्फ दारा सिंह की सजा में छूट संबंधी अर्जी पर फैसला लेने में देरी के लिए ओडिशा सरकार पर नाराजगी जाहिर की।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने ओडिशा सरकार की ओर से पेश वकील से कहा, 'आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं, लीजिए। अगर आप फैसला नहीं लेते हैं, तो हम फैसला सुनाएंगे। हम फैसला लेने से बचने की इस तरह की कोशिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते।'

दारा सिंह 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी स्टेंस और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा है।

बेंच कहा कि दारा सिंह 26 साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे है और मामले की सुनवाई बार-बार इसलिए स्थगित की गई, ताकि संबंधित प्राधिकरण को सजा में छूट के अनुरोध वाली उसकी अर्जी पर फैसला लेने का अवसर मिल सके। बेंच ने कहा कि 14 जुलाई को जब मामले की सुनवाई स्थगित की गई थी, तब राज्य सजा समीक्षा बोर्ड दारा सिंह की याचिका पर फैसला लेने की प्रक्रिया में था।

बीसीआई चेयरमैन को हटाने वकीलों का प्रदर्शन

नई दिल्ली। दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से किए जा रहे इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन मिला है। प्रदर्शन को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यालय के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है।

सराफा कारोबारियों ने रखा आधा दिन बंद, पीएमओ के नाम ज्ञापन

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। सोने की शुद्धता, ग्राहकों के हित और सराफा कारोबारियों के अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन आज गुरुवार को प्रदेशभर में ज्ञापन अभियान चला रहा है। बिलासपुर में आधे दिन सराफा बाजार बंद रहा। सभी 33 जिलों में सराफा कारोबारियों ने कलेक्टर के माध्यम से पीएमओ के नाम ज्ञापन सौंपा।

बिलासपुर में 14 अगस्त को हॉलमार्क वाले 22 कैरेट सोने के आभूषण जांच में पहली रिपोर्ट में 20 कैरेट शुद्धता बताई गई थी। दोबारा जांच में इसकी शुद्धता 916 यानी 22 कैरेट मिली। एसोसिएशन ने इसे सोने की जांच व्यवस्था और ग्राहकों के भरोसे से जुड़ा गंभीर मामला बताया है।

इलाज के बहाने महिला से छेड़छाड़, गिरफ्तार

बालोद। इलाज के लिए दवाखाने पहुंची एक महिला ने संचालक पर आरोप लगाया है कि उसने सायटिका के इलाज के बहाने दवाखाना का दरवाजा बंद कर उसके साथ छेड़छाड़ की। उसने इसका विरोध किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामला बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम झलमला स्थित बैद्यनाथ दवाखाना का है।

जिन सीमाओं की होती रही अनदेखी, अब वो टॉप प्रायरिटी

नई दिल्ली (ए.)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि देश की सीमा से सटे इलाके, जिनकी पहले अनदेखी की गई थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शीर्ष प्राथमिकता बन गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमाई इलाकों में विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

किरेन रिजिजू ने 'एक्स' पर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों माजा, गालेमो और तक्सिंग के दौरे का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में बुनियादी ढांचे के काम के लिए मशीनें चलती दिखीं।

केंद्रीय मंत्री ने सेना के जवानों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। वीडियो में दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ हिमालयी इलाका भी दिखा जो सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है।

'एक्स' पर पोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, 'कुछ लोग सीमा को लेकर लापरवाही से टिप्पणी कर देते हैं। सीमाई क्षेत्र मुश्किल हैं, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार सीमा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मैं अरुणाचल प्रदेश के माजा, गालेमो, तक्सिंग इलाकों में गया ताकि बुनियादी ढांचे के काम तेज किए जा सकें। पहले सीमाओं की अनदेखी हुई थी लेकिन अब यह शीर्ष प्राथमिकता है।'

वंदेमातरम् के अंतरों को लेकर दोनों दलों के बीच घमासान

भाजपा ने एक्स पर कांग्रेस को कहा 'नई मुस्लिम लीग'

नई दिल्ली (ए.)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंद मातरम के केवल दो छंद गाने के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी 'नई मुस्लिम लीग' बन गई है।

नवीन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस ने अब अपने अपमान को एक प्रस्ताव की शक्ल दे दी है। उसकी कार्य समिति ने तय किया है कि कांग्रेस के मंचों पर 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने 15 अगस्त को कांग्रेस कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाए जाने को लेकर हुए विवाद का भी इशारों में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब 'एक व्यक्ति के आचरण' में भी राष्ट्रगीत का यही अपमान दिखाई दिया था तब कांग्रेस ने उसे 'संयोग' बताया था। आज वही अपमान कांग्रेस की नीति बन चुका है। उन्होंने आगे लिखा, 'भारत माता' की इस पावन वंदना का अपमान उन हजारों बलिदानियों का तिरस्कार है, जिन्होंने इसी गीत को अपनी चेतना में रखकर राष्ट्र के लिए बलिदान दिया था। यह केवल एक राजनीतिक बचाव नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की भूख का प्रमाण है, जिसके आगे कांग्रेस ने हर बार राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरवी रखा है। कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है।

तो नेहरू-गांधी-पटेल पर करें एफआईआर

मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'वंदे मातरम' विवाद पर अपनी बात रखी थी। खरगे ने कहा था कि उन्होंने वही 'वंदे मातरम' गाया है, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी गाते थे। अगर यह अपराध है, तो गांधी जी, नेहरू और पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करें। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कहेंगे, वही देश का मानक बन जाएगा। कल कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ सकती है। अगर वह कुछ कहेगी, तो क्या वह नियम बन जाएगा?

समस्या सुलझाने विद्यार्थियों से ऑनलाइन चैट करेगा कृषि विश्वविद्यालय

रायपुर। कृषि विवि अब अपने छात्रों से ऑनलाइन चैटिंग करेगा। यह व्यवस्था छात्रों की समस्याएं यथाशीघ्र दूर करने की जा रही है। विद्यार्थियों को आधुनिक, त्वरित एवं सुविधाजनक डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में 'आईजीकेवी-कनेक्ट' व्हाट्सऐप आधारित चैटबॉट की शुरुआत की गई है। कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल ने विवि के समस्त विद्यार्थियों को स्वागत संदेश भेजकर आईजीकेवी-कनेक्ट के उपयोग के लिए प्रेरित किया। आईजीकेवी-कनेक्ट विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं सेवाएं व्हाट्सऐप के माध्यम से सहज और त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया है।

संपादकीय

अस्पताल में खौफ

जीवनदायी आरोग्यशाला में राक्षसी दुराचार

कोई भी अस्पताल बीमार व अशक्त लोगों के जीवन की अंतिम किरण होती है। एक विश्वास का प्रतीक कि वहां से स्वस्थ होकर लौटेंगे। तरह-तरह के रोगों से पीड़ितों का अस्पताल पर भरोसा होता है कि वहां पहुंचकर उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन यदि किसी अस्पताल में उपचार के लिये गई महिला के साथ जांच के नाम पर दुराचार हो और वीभत्स कृत्य उसे मौत के मुंह में धकेल दे तो इससे ज्यादा व भयावह कुछ नहीं हो सकता। यह घटना लाखों मजबूर-बीमार लोगों तथा महिलाओं के भरोसे को तोड़ती है, जब यह पता चलता है कि वीभत्स घटना एक सरकारी अस्पताल में हुई है। हरियाणा के पानीपत स्थित अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में एक 58 साल की महिला के साथ हुए दुराचार और उसके बाद रोहतक के पीजीआईएमएस में उपचार के दौरान उसकी मौत ने लाखों लोगों के भरोसे को भी तोड़ा है। निस्संदेह, कानून अपना काम करेगा, पुलिस की जांच अपराधी को सख्त दंड दिलाने में मददगार होगी, लेकिन इस घटना ने संस्थागत सुरक्षा इंतजामों की चिंताजनक नाकामी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि आरोपी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तरह अस्पताल की सीटी स्कैन और एमआरआई यूनिट चलाने वाली एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह कथित तौर पर सीटी स्कैन टेक्नीशियन का काम कैसे कर रहा था? निस्संदेह, सरकारी अस्पताल के अंदर इस तरह से दायित्वों की भूमिका में बदलाव होना व्यवस्था की ऐसी नाकामियों की तरफ इशारा करता है, जो किसी व्यक्ति के कुकृत्य से कहीं अधिक आगे की बात है। निस्संदेह, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अस्पताल व अन्य सार्वजनिक संस्थानों में देख-रेख, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के पालन और जवाबदेही को लेकर विचलित करने वाले सवाल खड़े करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा के बुनियादी नियम-कानून एक साथ निरर्थक हो गए हैं।

> “ हरियाणा के पानीपत स्थित अस्पताल के सीटी स्कैन रूम में एक 58 साल की महिला के साथ हुए दुराचार और उसके बाद रोहतक के पीजीआईएमएस में उपचार के दौरान उसकी मौत ने लाखों लोगों के भरोसे को भी तोड़ा है। निस्संदेह, कानून अपना काम करेगा, पुलिस की जांच अपराधी को सख्त दंड दिलाने में मददगार होगी, लेकिन इस घटना ने संस्थागत सुरक्षा इंतजामों की चिंताजनक नाकामी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। सबसे अधिक विचलित करने वाली बात यह है कि आरोपी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तरह अस्पताल की सीटी स्कैन और एमआरआई यूनिट चलाने वाली एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था।

सवाल यह है कि पहले ही रोगों, शारीरिक जीर्णता, मानसिक तनावों से गुजर रहे लोगों की सुरक्षा हेतु क्या कोई कायदे-कानून नहीं हैं? उनकी सुरक्षा महज राम भरोसे है? सरकारी अस्पतालों में मरीजों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं और पक्की नौकरी वालों का आमतौर पर मरीजों से व्यवहार कैसा होता है, वह सर्वविदित है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें मरीज के साथ स्कैन-रूम में नहीं जाने दिया गया। वहां कोई महिला स्टॉफ मौजूद नहीं थी। दुर्भाग्य से महिला मरीज को ऐसे व्यक्ति के भरोसे छोड़ दिया गया, जिसे वास्तव में वहां खड़े रहने का भी हक नहीं था। ये चिकित्सा प्रक्रिया की कोई मामूली चूक नहीं है। ऐसी खामी में शोषण का खतरा लगातार बना रहेगा। विगत में भी कई ऐसी घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान खींचा, जहां महिलाओं के साथ यौन हिंसा हुई। वर्ष 1973 में मुंबई के केईएम अस्पताल में नर्स अरुणा शानबाग के साथ जानलेवा यौन-हिंसा हुई थी। इसी तरह की कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कालेज की दुखद घटना, जिसमें यौन हिंसा से मेडिकल की छात्रा की मौत हुई थी। विडंबना यह कि घटना का जमकर राजनीतिक दोहन तो होता है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होते ही सुधार के वायदे भी हवा हो जाते हैं। एक बार फिर पानीपत की दुखद घटना ने बताया है कि हमारे नीति-नियंताओं की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। निश्चित रूप से पानीपत में हुई वीभत्स घटना को महज एक अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस घटना के मद्देनजर मरीजों की सुरक्षा से जुड़े नीतिगत फैसलों में बदलाव लाया जाना चाहिए। ऐसे अस्पताल व सार्वजनिक सेवा केंद्रों से जुड़े, प्रत्येक आउटसोर्स किए गए विकल्पों की समीक्षा की जानी चाहिए। तैनात कर्मचारियों की कारगुजारियों-भूमिकाओं का सत्यापन किया जाना चाहिए। अस्पतालों में सीसीटीवी कवरेज का दायरा विस्तृत व मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही अनिवार्य रूप से सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का प्रोटोकॉल लागू किया जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी में जवाबदेही से बचने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि स्वास्थ्य सेवा में उपचार के साथ लोगों के भरोसे को बनाये रखना भी अनिवार्य शर्त है।

प्राकृतिक खेती - सतत कृषि और आत्मनिर्भरतो की ओर बढ़ते कदम

डॉ. देवेश चतुर्वेदी

भारत ने पिछले दशक में कृषि क्षेत्र में तेज प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, पिछले 5 सालों में विकास दर 4% से अधिक रही है। खाद्यान्न, बागवानी और तेलहन फसलों का बंपर उत्पादन हुआ है। यह किसानों द्वारा नई तकनीकों को अपनाने और सिंचाई वाले क्षेत्र का विस्तार, बेहतर जल उपयोग दक्षता और समय पर व पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्धता जैसी सरकार की ठोस नीतियों के समर्थन का परिणाम है। बागवानी फसलों की हिस्सेदारी भी काफी बढ़ रही है और इसकी विकास दर अपेक्षाकृत अधिक है।

हालांकि, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता में गिरावट और प्रमुख फसलों की उत्पादकता में स्थिरता आ रही है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (एनयूई) में धीरे-धीरे आई कमी के कारण एक ऐसा दुष्चक्र बन गया है, जिसमें किसान रासायनिक खादों की मात्रा तो लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्पादकता में बहुत मामूली बढ़ोतरी ही हो रही है।

सरकार की मृदा स्वाथ्य और उर्वरक योजना के तहत 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों का वितरण किया गया है। इससे प्राप्त डेटा के अखिल-इंडिया विश्लेषण से चिंताजनक बात सामने आई है कि मिट्टी में जैविक कार्बन (एसओसी) और अन्य जरूरी सूक्ष्म-पोषक तत्वों की भारी कमी है। स्वस्थ मिट्टी में एसओसी 1% से अधिक होना चाहिए, लेकिन यह औसतन 0.5% के आसपास है और कुछ क्षेत्रों में यह 0.3% तक के यह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है।

कम मात्रा में एसओसी से मिट्टी की सरंध्रता कम हो जाती है, जिसका दोहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है: पानी का जमीन में रिसाव और जल धारण क्षमता, दोनों में कमी आती है। परिणामस्वरूप, वर्षा और सिंचाई का पानी बह जाता है, जो ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है और न तो यह जमीन के नीचे जाकर भूजल स्तर बढ़ा पाता है और न ही पौधों की वृद्धि के लिए आसानी से उपलब्ध रहता है।

कम एसओसी का एक और नकारात्मक प्रभाव यह है कि ऐसे मिट्टी पर उगाए जाने वाले पौधों की पोषक तत्व अवशोषण क्षमता कम हो जाती है। समान उत्पादकता स्तर तक पहुँचने के लिए अधिक से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। रासायनिक उर्वरकों की बढ़ी हुई खुराक उर्वरक उपयोग दक्षता को और कम कर देती है, जिससे मृदा-स्वास्थ्य का नुकसान होता है और देश रासायनिक उर्वरकों या उनके घरेलू उत्पादन के कच्चे माल को आयात करने में अपनी कीमती विदेशी मुद्रा खर्च करता है।

अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के असंतुलित उपयोग ने उन लाभकारी सूक्ष्मजीवों और कीड़ों को भी कम कर दिया है, जो मिट्टी की सरंध्रता को बेहतर बनाने और गहरी मिट्टी से पोषक तत्वों को ऊपरी मिट्टी तक स्थानांतरित करने में मदद करते हैं, ताकि पौधे उन्हें अवशोषित कर सकें।

एक अन्य चिंताजनक प्रभाव उपज की गुणवत्ता और सुरक्षा पर पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि रसायन खाने-पीने और पशु चारे की श्रृंखला में पहुँच जायेंगे और आखिरकार मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करेंगे। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें फलों, सब्जियों, अनाज और अन्य वाणिज्यिक फसलों में कीटनाशकों का न्यूनतम अवशेष स्तर तय सीमा को पार कर गया है, जिसके चलते निर्यात की खेपें रद्द होती हैं और वैश्विक बाजार में ब्रांड इंडिया की छवि पर बुरा पड़ता है।

हालांकि ये चिंताएँ कुछ समय से व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन सरकार ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य सतत कृषि के लिए पशुधन या गाय आधारित रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है, ताकि मिट्टी की सेहत खासकर एसओसी में सुधार हो सके, पौष्टिक तत्वों के अवशोषण की क्षमता बढ़ सके और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों पर देश की निर्भरता कम हो सके।

प्राकृतिक खेती, जिसे इसके समर्थकों द्वारा आमतौर पर 'जीरो बजट खेती' कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक पर आधारित है, जिसे किसानों ने कई सालों तक आज़माया और परखा है तथा इसे मान्यता दी है। इसके परिणाम भी बहुत उत्साहजनक रहे हैं। यह एक समग्र तकनीकी समाधान पर आधारित है, जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया जाता है, जैसे स्थानीय नस्ल की गाय का गोबर और गोमूत्र, जिनकी लागत किसान के लिए लगभग शून्य होती है।

बीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाला बीजामृत सूत्र बेहतर अंकुरण और मजबूत पौधों में मदद करता है, जबकि जीवामृत, घन-जीवामृत और सप्तयांकुर का उपचार मित्र सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी और मृदा-उत्पादकता को काफी बढ़ा देता है। पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा सौंठास्त्र और खट्टी लस्सी के इस्तेमाल से की जाती है, जो बैक्टीरिया और फफूंद संक्रमण को रोकते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के कीड़ों और कीट को नियंत्रित करने के लिए 'नीमास्त्र', 'ब्रह्मास्त्र', 'अग्निअस्त्र' और 'दशपर्णी अर्क' का प्रयोग किया जाता है।

उपरोक्त सभी उपचारों की सावधानीपूर्वक तैयारी और उचित मात्रा में उपयोग से मिट्टी की सेहत के बेहतर परिणाम मिले हैं और उत्पादकता पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है, जबकि उपज की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मिशन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से प्रगति कर रहा है, जिसका लक्षित क्षेत्र 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक है और यह 18 लाख से अधिक किसानों को कम से कम 50 हेक्टेयर के क्लस्टर में कवर करता है। कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की टीम, जिसे किसान प्रशिक्षक और कृषि सखी संसाधन व्यक्ति के रूप में सहायता प्रदान कर रहे हैं, किसानो को जागरूक कर रही है, प्रशिक्षण दे रही है और इस खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

जिन किसानों के पास स्थानीय नस्ल की गायें हैं, उन्हें खेत पर ही इन उपचारों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, बड़ी संख्या में जैव-इनपुट संसाधन केंद्र भी मुख्य रूप से स्थानीय डेयरियों या पशु आश्रय गृहों के निकट स्थापित किए गए हैं, ताकि ये उपचार किसानों को मामूली कीमत पर उपलब्ध कराए जा सकें।

यह मिशन विज्ञान-आधारित रणनीति के माध्यम से लागू किया जा रहा है, ताकि किसान इन प्रथाओं को बिना किसी संदेह या हिचकिचाहट के अपना सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने क्षेत्र और फसल-विशिष्ट क्षमता मानचित्र विकसित किए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्राकृतिक खेती कहाँ प्रभावी होगी। आईसीएआर के संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में इस देसी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए इसकी प्रभावशीलता को वैज्ञानिक रूप से मान्यता देने के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। आईसीएआर संस्थानों की निगरानी में किए गए कई प्रयोगों ने कई फसलों के लिए बहुत सकारात्मक परिणाम दिए हैं और अब मिशन के ज़रिए इनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

प्राकृतिक उत्पादों का विपणन एक और महत्वपूर्ण रणनीति है, जो किसानों की आय में वृद्धि करेगी और उन्हें इन प्रथाओं को जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी। राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक कृषि केंद्र (एनसीओएनएफ) ने प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणीकरण नियम बनाये हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने पहले ही सहभागी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए हैं, जिससे वे अपने प्रमाणित विशिष्ट उत्पाद को ऊंची कीमतों पर बेच सकते हैं।

एक तरफ जहां इस मिशन के तहत प्रमाणन, विपणन और ब्रांडिंग के साथ शुद्ध प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक हाइब्रिड मॉडल को प्रोत्साहन देने की रणनीति में यह दिखाया गया है कि प्राकृतिक खेती की प्रथाओं को अपनाने और रासायनिक उर्वरकों की खुराक को कम करने से भी लंबे समय तक उत्पादकता बनी रह सकती है और मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इस मॉडल को व्यापक स्वीकार्यता मिल सकती है। इसे अपनाने वाले किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाइब्रिड मॉडल में प्राकृतिक खेती की प्रथाओं को अपनाने से रासायनिक उर्वरकों पर धीरे-धीरे निर्भरता कम होती है। यहाँ तक कि कुछ समय बाद, किसान कई फसलों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर सकते हैं और फिर भी उतनी ही पैदावार और आमदनी बनाए रख सकते हैं।

मध्य पूर्व में चल रहे मौजूदा संकट से पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से सात सूत्रीय अपील की है, जिनमें रासायनिक खाद का समझदारी से इस्तेमाल और प्राकृतिक खेती को अपनाना शामिल हैं। एक ओर जहाँ प्राकृतिक खेती को अपनाने से खेती में स्थायित्व आ रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे पशुधन के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने में भी मदद मिल रही है, जिनका आम तौर पर दूध देने की उम्र खत्म होने के बाद परित्याग कर दिया जाता है। इसका एक और फायदा यह है कि घरेलु उपभोग और निर्यात के लिए सुरक्षित भोजन मिलता है, साथ ही देश की कीमती विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है।

(लेखक भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव हैं)

बहुत सारे नए रोजगार भी क्रिएट करेगा एआई

रघुराम राजन

क्या एआई हमारी नौकरियां खाने जा रहा है? अभी तो कोई नहीं जानता कि यह कितनी तेजी से होगा, कितना व्यापक होगा और इसका सबसे अधिक असर किन सेक्टर्स पर पड़ेगा। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि अलग-अलग कंपनियां इस तकनीक को अपने कामकाज में कितनी तेजी से लागू करती हैं।

अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के हालिया बिजनेस ट्रेंड्स एंड आउटलुक सर्वे के अनुसार, 20 से कम कर्मचारियों वाली केवल 20% कंपनियां ही वर्तमान में एआई का इस्तेमाल करती हैं, जबकि कम से कम 250 कर्मचारियों वाले 37% बिजनेसों में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी बड़ी कंपनियां इस तकनीक का अधिक उपयोग कर रही हैं, लेकिन 37% का आंकड़ा भी कम ही है।

फिलहाल, एआई को अपनाने की राह में एक बड़ी बाधा यह है कि पहले से ही असाधारण क्षमताओं वाली इस तकनीक को मौजूदा वर्कफ्लो में इस तरह से कैसे समायोजित करें कि कंपनियां उसका पूरा लाभ उठा सकें। इसके लिए ऐसे मॉडल जरूरी हैं, जो न केवल मौजूदा डेटा पर प्रशिक्षित हों, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल से पैदा होने वाले नए डेटा के प्रति एडाप्टिव भी हों।

एआई को अपनाने में बाधा डालने वाला एक अन्य फैक्टर लागतों को लेकर अनिश्चितता है। कई बड़ी कंपनियां अभी भी पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं और नियुक्ति या छंटनी के फैसले टाल रही हैं, क्योंकि वे स्थिति के और स्पष्ट होने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन प्रतिस्पर्धात्मक दबाव उन्हें इस तकनीक को अपनाने के लिए मजबूर करेगा ही।

इसके बावजूद, रोजगार के लिहाज से भविष्य पूरी तरह निराशाजनक नहीं है। अगर कंपनियां वही वस्तुएं बनाती और वही सेवाएं उपलब्ध कराती रहती हैं- जो वे अभी करती हैं- तो एआई को अपनाने का प्रभाव वही होगा, जो किसी भी नई तकनीक का होता है। हां, कुछ नौकरियां जरूर गैर-जरूरी हो जाएंगी, लेकिन कुछ अधिक प्रोडक्टिव और दिलचस्प भी होंगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि एआई ऊबाऊ और दोहराव वाले कामों को कम करेगा और उन कामों में मदद करेगा, जिन्हें इंसान ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं।

साथ ही, नई नौकरियां भी पैदा होंगी- जैसे एआई इंजीनियरों की, जो इस तकनीक के इंप्लीमेंटेशन की निगरानी करेंगे। इसके अलावा, अगर एआई को अपनाने की वजह प्रोडक्टिविटी में वृद्धि है (यह नहीं कि यह मानव-श्रम की तुलना में सस्ता पड़ता है), तो कंपनियों की कम लागत में अधिक उत्पादन करने की क्षमता उन्हें कीमतें घटाने और बिक्री बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। यह प्रसिद्ध जेवन्स-इफेक्ट है और इससे रोजगार भी बढ़ने चाहिए। आशावादी होने का एक और कारण यह है कि एआई नए बिजनेस खड़े करने में मदद कर सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फर्नीचर बनाने का कारोबार शुरू करना चाहता है, लेकिन वह इसलिए हिचकिचाता है क्योंकि इसके लिए उसे एक वेब-प्रोग्रामर और अकाउंटेंट की जरूरत है। अगर एआई ये दोनों भूमिकाएं निभा सके, तो शायद वह काफी कम लागत में एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय शुरू कर सकता है। महामारी के दौरान स्टार्टअप की संख्या पहले ही काफी बढ़ गई थी और हाल की तिमाहियों में इसमें और वृद्धि हुई है। अर्थशास्त्री डेविड ऑटर बताते हैं कि एआई मध्यम कौशल वाले कामगारों को हाई-स्किल्स से लैस कर सकता है।

इसका उदाहरण कोई नर्स प्रैक्टिशनर है, जो मेडिकल एआई की मदद से कहीं अधिक बीमारियों की पहचान और इलाज कर सकती है। दुनिया भर में चिकित्सा-सेवाओं की भारी मांग को देखते हुए इस क्षेत्र में नए रोजगार पैदा करने की काफी गुंजाइश है। यह समझते हुए कि एआई के कारण नौकरियों के संकट का पहला दौर आखिरी नहीं होगा, कंपनियों को समय-समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और जहां तक संभव हो, उन्हें नौकरी पर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत होगी। सरकारें कर्मचारियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए टैक्स-क्रेडिट पर विचार कर सकती हैं, जिसमें कर्मचारी के काम पर बने रहने पर हर साल प्रशिक्षण की लागत का एक-तिहाई इस्तेमाल किया जा सके।

अगर सरकार ऐसी नीति एआई अपनाने वाली कंपनियों पर लागू करना चाहती है, तो वो यह भी कर सकती है कि इस क्रेडिट का इस्तेमाल केवल टोकन टैक्स की भरपाई के लिए हो। हालांकि, कर-प्रोत्साहनों से भी अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि कंपनियां स्वीकारें वे अपने कर्मचारियों को अनिश्चित भविष्य से निपटने में मदद करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जैसे-जैसे रोजगार को लेकर अनिश्चितता बढ़ेगी, सबसे योग्य और प्रतिभाशाली लोग भी ऐसे एम्प्लॉयर के यहां नौकरी स्वीकार करने को लेकर चिंतित हो सकते हैं, जो जब चाहे उन्हें नौकरी से निकाल सकता है।

एनालॉग पनीर को लेकर उपभोक्ताओं में असमंजस

पंकज चतुर्वेदी

उपभोक्ता के लिए फिलहाल सबसे भरोसेमंद तरीका यही बचता है कि खरीदते समय पैकेट पर लिखी सामग्री ध्यान से पढ़ें और किसी जाने-पहचाने विश्वसनीय स्रोत से ही दूध उत्पाद खरीदें।

देश में एक अजीब विरोधाभास खुलकर सामने आया है। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर को कभी गैरकानूनी नहीं ठहराया, बल्कि उसे बनाने और बेचने की छूट दी, बस इतनी शर्त रखी कि पैकेट पर साफ-साफ लिखा हो कि यह असली दूध से नहीं बना है। इसके बावजूद महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है, जबकि दूसरे सबसे बड़े दूध उत्पादक राज्य राजस्थान में इसके निर्माण और बिक्री पर आज भी कोई रोक नहीं है। यही उलझन अब उपभोक्ताओं से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की चिंता का विषय बन गई है।

एनालॉग पनीर देखने, स्वाद और बनावट में बिल्कुल असली दूध के पनीर जैसा लगता है, लेकिन इसे बनाने में दूध की चर्बी या दूध के प्रोटीन की जगह वनस्पति तेल, स्टार्च, सोया या मटर के प्रोटीन और चिपकाने वाले पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं-कहीं तो सोडा और वनस्पति घी से नकली दूध और फ्रेंच चॉक यानी सेलखड़ी से नकली मावा तक तैयार किया जा रहा है। इसकी लागत असली पनीर से कहीं कम आती है, इसलिए होटल, ढाबों, रेस्तरां और खानपान के बड़े कारोबार में इसका खुलकर इस्तेमाल हो रहा है। समस्या तब पैदा होती है जब इसे उसी कीमत पर, बिना किसी सूचना के, असली दूध के पनीर के नाम पर बेचा जाता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते आए हैं कि इस तरह के उत्पादों में मिलने वाली औद्योगिक चर्बी हृदय रोग का खतरा बढ़ाती है और इससे शरीर को कोई पोषण संबंधी लाभ नहीं मिलता। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि इस तरह की औद्योगिक चर्बी का कोई ज्ञात स्वास्थ्य लाभ नहीं है। इसके नियमित सेवन से पेट में संक्रमण, अम्लता, यकृत पर बुरा असर और खराब वसा का स्तर बढ़ने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। साथ ही इसमें असली दूध के मुकाबले प्रोटीन और कैल्शियम कम, जबकि सोडियम और शोधित

स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे उपभोक्ता कीमत तो दूध के पनीर जितनी चुकाता है, लेकिन पोषण उतना नहीं पाता।

केंद्र सरकार का रुख शुरू से ही सतर्क रहा है। उसने इसे पूरी तरह हानिकारक मानने से इनकार किया है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इसके उत्पादन पर कभी रोक नहीं लगाई गई। महाराष्ट्र की पहल के बाद केंद्रीय प्राधिकरण ने एक परिपत्र जरूर जारी किया, जिसमें होटलों को अपने भोजन-सूची में यह बताना अनिवार्य किया गया कि इस्तेमाल हो रहा पनीर असली है या एनालॉग। लेकिन व्यवहार में यह नियम बाजार में बहुत कम ही लागू होता दिखा, क्योंकि खुले बाजार में बिना किसी सूचना के यह उत्पाद खपता रहा।

यही वजह रही कि कई राज्य सरकारों ने केंद्र के नरम रुख से आगे बढ़कर सख्त कदम उठाए। छत्तीसगढ़ में तीस जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री ने एनालॉग पनीर के इस्तेमाल और बिक्री पर सीधी रोक की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा कि सेहत से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा और राज्य में इसके निर्माण-बिक्री पर पाबंदी लगाई जाएगी, साथ ही प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र भी एनालॉग पनीर, चीज और मक्खन के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इन राज्यों का कहना है कि जब तक निर्माण पर ही रोक नहीं लगेगी, तब तक अकेले सूचना अंकन का नियम बेईमान कारोबारियों को धोखाधड़ी से नहीं रोक पाएगा।

इसके उलट राजस्थान में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश के कुल दूध उत्पादन में लगभग पंद्रह प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ यह दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, फिर भी यहां पनीर, मावा, घी जैसे एनालॉग उत्पादों के निर्माण-बिक्री पर अलग से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। यहां केवल सामान्य मिलावट जांच के दायरे में ही इसकी निगरानी हो रही है। पिछले वर्ष राज्य में हजारों खाद्य नमूनों की जांच हुई और इनमें से बड़ी संख्या में नमूने तय मानकों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन इनमें दूध और मावा से जुड़ी मिलावट का अलग ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया।

दरअसल, एनालॉग पनीर पर अंकन को लेकर बरती जा रही ढिलाई सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी का कारण भी बनी। अदालत ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और खासकर बच्चों के स्वास्थ्य से किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जा सकता, और केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कानून की नजर में सही ढंग से सूचित करके बेचा गया एनालॉग पनीर आज भी गैरकानूनी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंध की बजाय पारदर्शिता के दायरे में रखा है। लेकिन बाजार की हकीकत कुछ और बताती है, जहां यह उत्पाद अक्सर बिना किसी सूचना के, असली दूध के पनीर के भाव पर बेचा जा रहा है। यही अंतर है जिसने कई राज्य सरकारों को केंद्र से आगे बढ़कर सीधी पाबंदी लगाने पर मजबूर किया, जबकि राजस्थान जैसे राज्य अभी भी पुराने ढांचे पर ही भरोसा जताए हुए हैं। उपभोक्ता के लिए फिलहाल सबसे भरोसेमंद तरीका यही बचता है कि खरीदते समय पैकेट पर लिखी सामग्री ध्यान से पढ़ें और किसी जाने-पहचाने विश्वसनीय स्रोत से ही दूध उत्पाद खरीदें।

रणछोड़दास हुए तो पार्क के बेंच पर बैठोगे

संसद लोकतंत्र का क्लासरूम है। जनता द्वारा चुने गये सांसद वहां के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी की अटेंडेंस इसलिए ज़रूरी है कि उसका भविष्य खराब न हो। सांसद की हाजिरी इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए कि देश का भविष्य खराब न हो। घर में रोज़ खड़का होता है। कभी-कभी तो पूरा खड़दू। कभी घरवाले ने लुगाई की बात नहीं सुनी, कभी सास-बहू आमने-सामने और कभी बाप-बेटा एक-दूसरे से दो-दो हाथ करने को तैयार। पर मजाल है कि घर का कोई सदस्य गुस्से में घर छोड़कर भाग जाए। आखिरकार घर का झगड़ा घर में ही निपटाया जाता है। लेकिन संसद का मामला बड़ा विचित्र है। मानो संसद नहीं, नाराज प्रेमी का व्हाट्सएप ग्रूप हो। एक मनचले का कहना है कि बात पसंद न आई तो संसद छोड़ दी। भाई, यो लोकतंत्र सै, तेरे साले की बारात नहीं सै जो रूठने फूफ्फे की ढाल मुंह सुजा कै बाहर खड़ा हो लिया! सरकार की बात पसंद नहीं आती तो फेर अंदर बैठ कै ऐसी-तैसी कर देते सरकार की! बाहर आकै तो कैमरां की ऐसी-तैसी कर रे हो।

घर इसलिए चलता है क्योंकि वहां लोग एक-दूसरे से नाराज होकर भी एक-दूसरे के साथ रहते हैं। संसद भी आखिर देश का सबसे बड़ा घर है। हाथ जोड़-जोड़ कर वोट मांगे, करोड़ों फूंके और जनता ने इन्हें सांसद की कुर्सी पर बिठा दिया। पर कुछ तो ऐसे हैं कि भीतर टिक ही नहीं रहे। बहाने ले-लेकर बाहर भाग रहे हैं। क्लास से बाहर निकलने पर स्कूल के बच्चे की अटेंडेंस कटती है, कॉलेज के विद्यार्थियों को डांट पड़ती है पर संसद से बाहर निकलने पर नेताओं के लिये फटकार क्यों नहीं है? संसद में तो विरोध और भी शानदार ढंग से किया जा सकता है। कुर्सी पर बैठे-बैठे विरोध कीजिए। तथ्यों से विरोध कीजिए। प्रश्नों से विरोध कीजिए। तर्कों से विरोध कीजिए। बहस से सरकार को घेर लो। संसद का असली सौंदर्य यही है कि विरोध भी सदन के भीतर हो और लोकतंत्र भी सदन के भीतर चले। संसद लोकतंत्र का क्लासरूम है। जनता द्वारा चुने गये सांसद वहां के विद्यार्थी हैं।

विद्यार्थी की अटेंडेंस इसलिए ज़रूरी है कि उसका भविष्य खराब न हो। सांसद की हाजिरी इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए कि देश का भविष्य खराब न हो। जनता ने इन नवाबों को संसद में बहस करने के लिए चुना है, बहस से भागने के लिए नहीं। अगर हर असहमति पर बाहर ही निकलना है तो अगली बार जनता इन्हें संसद नहीं, पार्क की बेंच पर बैठा देगी।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

नव प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के लिए 'नव कौशल पथ' कार्यक्रम का आयोजन

भिलाई। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) भिलाई में विगत दिवस नव प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो दिवसीय 'नव कौशल पथ-नई राह, नया हुनर' इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के नियम-अनुशासन, प्लेसमेंट, अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा में लेटरल एंट्री, ओजेटी एवं सीबीटी परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी दी गई। आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भिलाई से प्राप्त जानकारी अनुसार करियर गाइडेंस एवं जॉब मार्केट ओरिएंटेशन के दौरान विशेषज्ञों ने बदलते रोजगार बाजार, प्रभावी बायोडाटा-सीवी, संचार एवं साक्षात्कार कौशल तथा आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स पर मार्गदर्शन दिया। पूर्व सफल प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा कर विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर सोनल डेविड सहित रोजगार विभाग, उद्योग एवं एल्यूमनी एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्राचार्य टी.एस. तवर के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में दुर्ग के जीतेश बने स्ट्रांग मेन ऑफ इंडिया

दुर्ग। यूनाईटेड पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में किया गया। इसमें दुर्ग की टीम ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में अपना वर्चस्व बरकरार रखा। टीम ने कुल 4 स्वर्ण पदक, 1 कांस्य पदक जीतकर दुर्ग शहर एवं छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। 56 किलोग्राम वर्ग समूह में सब जूनियर-जीतेश यादव ने स्वर्ण पदक, 62 किलोग्राम वर्ग समूह में जूनियर-प्रभाष नेताम ने स्वर्ण पदक, इसी वर्ग समूह में जूनियर पूर्वज यादव ने कांस्य पदक, 69 किलोग्राम वर्गसमूह में जूनियर वर्ग में ऋषभ यादव ने पुन: स्वर्ण पदक, तथा महिला खिलाड़ी प्रिया सिंह ने जूनियर, 64 किलोग्राम वर्गसमूह में स्वर्ण पदक हासिल किया।

आईटीआई दुर्ग में आयोजित रोजगार मेला में 130 अभ्यर्थियों का चयन

दुर्ग। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 10 नियोक्ता कंपनियों की कुल 700 रिक्त पदों के लिए लगभग 1026 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। इनमें से 300 अभ्यर्थियों ने मेला स्थल पर उपस्थित हुए। इनमें से 130 अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक रूप से किया गया। अंतिम चरण के लिए 55 अभ्यर्थी चयनित हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोजगार कार्यालय के ईश्वर प्रसाद साहू, शिवदयाल धृतलहरे, संत्री ठाकुर, दुलेश्वर साहू उपस्थित थे। संस्था के मिथलेश सोनखुटिया, स्वीटी शर्मा, यामिनी साहू, देवी लाल साहू, जितेंद्र, महेंद्र, राजेंद्र तथा एमएमवी के प्रशिक्षणार्थी निखिल कुमार, प्रमोद यादव आदि उपस्थित रहे।

दूसरों से सम्मान, प्रेम और खुशी मांगें नहीं, निस्वार्थ भाव से बांटें : ब्रह्मकुमार सूरज भाई

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा सेक्टर-7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में आयोजित दो दिवसीय योग कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक एवं पीस ऑफ माइंड चैनल के सुप्रसिद्ध कार्यक्रम समाधान के मुख्य वक्ता ब्रह्माकुमार सूरज भाई ने अपने अनुभव साझा किए।

इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मनुष्य अपने जीवन में सम्मान, प्यार, खुशी, स्नेह और शांति चाहता है, लेकिन विडंबना यह है कि वह इन्हें दूसरों से चाहता है। उन्होंने कहा कि ये चीजें मांगने से नहीं मिलतीं, बल्कि इन्हें निस्वार्थ भाव से दूसरों को देने से जीवन में वास्तविक सुख और शांति का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में देवी-देवताओं और भगवान वरदाता के रूप में विराजित है, जो बिना किसी

अपेक्षा के सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने इष्ट व परमात्मा से शक्ति लेकर दूसरों को प्रेम और खुशी का दान देना चाहिए।

ब्रह्माकुमार सूरज भाई ने पवित्र सावन मास का आध्यात्मिक संदेश देते हुए कहा कि परमात्मा शिव पर क्रोध, लोभ और लालच जैसे तीन अवगुणों का दान करें तथा अपने मानस पटल पर सदैव सुंदर एवं श्रेष्ठ विचारों का सृजन करें। दो दिवसीय योग एवं तपस्या कार्यक्रम में साधकों ने अपने जीवन में आने वाली विभिन्न परेशानियों एवं चुनौतियों को प्रश्नों के माध्यम से साझा किया और उनके समाधान प्राप्त किए।

कार्यक्रम में डिवाइन ग्रुप के बच्चों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। आबू पर्वत से पधारे ब्रह्माकुमार रुपेश भाई एवं ब्रह्माकुमारी गीता दीदी ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंत में भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्माकुमारी राजयोगिनी आशा दीदी ने आभार व्यक्त किया। योग कार्यक्रम में भिलाई के सभी सेवा केंद्रों से बड़ी संख्या में साधकों ने लाभ लिया।

सिंचाई नहर का रास्ता रुकने से किसान परेशान, कलेक्टर सिंह से लगाई गुहार

■ **कलेक्टर जनदर्शन में विभिन्न समस्याओं का हुआ समाधान**

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्राम खेदामारा (नवातरिया) थाना जामुल के किसानों ने सिंचाई के पानी का रास्ता बाधित किए जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर सोनल डेविड भी उपस्थित थे।

जनदर्शन में ग्राम पंचायत सोरम तहसील पाटन निवासी ने शासकीय तालाब को निस्तारी के लिए सुरक्षित रखे जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरपंच द्वारा बिना कोई प्रस्ताव पारित किए मछली पालन के लिए अनुमति दे दी गई है। इससे तालाब का पानी दूषित हो रहा है और ग्रामीणों को निस्तारी में परेशानी हो रही है।

400 एकड़ कृषि भूमि तक नहीं पहुंच रहा पानी

सिंचाई नहर को लेकर किसानों ने बताया कि अवैध प्लाटिंग एवं मकान निर्माण के चलते नहर से करीब 400 एकड़ कृषि भूमि तक पहुंचने वाला पानी के रास्ते को बंद कर दिया गया है इससे लगभग 30 किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। भवन निर्माण से पहले संबंधित व्यक्ति को नहर से सिंचाई के लिए आने वाले पानी के निकासी हेतु नाली निर्माण की व्यवस्था करने को कहा गया था, किन्तु उक्त सिंचाई मार्ग को बंद कर दिया गया, जिसके कारण कृषि कार्य बाधित हो रहा है। किसानों ने नाली निर्माण कर सिंचाई व्यवस्था बहाल कराने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

जनदर्शन में मिले 115 आवेदन

जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित 115 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

ई-केवाईसी के बाद भी नहीं मिल रहा राशन

इसी कड़ी में जामुल के लवकुश नगर वार्ड निवासी ने बीपीएल राशन कार्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद पिछले नौ माह से राशन नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2025 से लगातार उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। शासन के निर्देशानुसार ई-केवायसी की प्रक्रिया भी कई बार पूरी कराई गई, इसके बावजूद पोर्टल पर नाम प्रदर्शित होने के बाद भी राशन का आबंटन नहीं किया जा रहा है। लंबे समय से राशन नहीं मिलने के कारण परिवार को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को नियमानुसार परीक्षण कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

भिलाई स्टील प्लांट में नया टॉरपीडो लैडल कार टीडी 2 का कमीशन

■ **हॉट मेटल परिवहन में आएगी तेजी, लॉजिस्टिक दक्षता होगी मजबूत**

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपनी परिचालन एवं लॉजिस्टिक क्षमता को सुदृढ़ करते हुए टॉरपीडो फ्लीट में नए टॉरपीडो लैडल कार 'टीडी2' को सफलतापूर्वक कमीशन किया। इसके साथ ही संयंत्र में टॉरपीडो लैडल कारों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो गई है। नई टॉरपीडो लैडल कार के शामिल होने से हॉट मेटल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी और विभिन्न परिचालनों के बीच लॉजिस्टिक दक्षता को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), राकेश कुमार तथा विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (आयरन), तापस दासगुप्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी (एमएंडयू), विजय कुमार बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक (मैकेनिकल), विवेक वर्मा एवं मुख्य महाप्रबंधक (बीएफ), मनोज कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यपालक निदेशक राकेश कुमार ने टीडी 2 की सफल कमीशनिंग के लिए टीम को बधाई देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की।

TD2 की सफल कमीशनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहायक महाप्रबंधक (बीएफ), अजयण एवं सहायक महाप्रबंधक (आरईडी),मोहम्मद साबिर के योगदान को विशेष रूप से सराहा गया। उनके समर्पण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सक्रिय सहभागिता ने परियोजना को समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से परिचालन में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए इसे परिचालन उत्कृष्टता और समन्वित टीम प्रयास का अनुकरणीय उदाहरण बताया। इस अवसर पर सभी संबंधित विभागों ने आपसी समन्वय को और मजबूत करते हुए संयंत्र की आगामी परिचालन उपलब्धियों के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

नगर निगम भिलाई की कार्रवाई : गंदगी फैलाने वालों पर 3 हजार का जुर्माना

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम के जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25 जवाहर नगर गौरव पथ मार्ग के पास गंदगी फैलाते पाए जाने पर रजनी ट्रेडर्स के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने मौके पर निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान द्वारा आसपास गंदगी फैलाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए 3,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। निगम अधिकारियों ने प्रतिष्ठान संचालकों एवं नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने तथा स्वच्छता व्यवस्था बनाए

रखने की अपील की। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

आंगनबाड़ी भवनों के लिए 28.38 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति

दुर्ग। जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास और बच्चों की सुरक्षा व बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में तत्परता से त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत हाल ही में सोनपुर मिडिल स्कूल भवन के प्लास्टर झड़ने की घटना तथा करेला व केसरा में आंगनबाड़ी भवनों की आवश्यकता संबंधी समाचारों एवं जन-अपेक्षाओं को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के अनुमोदन पश्चात् जिला पंचायत दुर्ग द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत पाटन के प्रस्ताव पर त्वरित स्वीकृति प्रदान करते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (व्हीबीजीरामजी) योजना तथा जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से कुल 28.38 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। जारी आदेश के तहत ग्राम सोनपुर में विद्यार्थियों की सुविधा एवं अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता को देखते हुए 5.00 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष (शेड निर्माण) की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, ग्राम केसरा एवं करेला में 11.69-11.69 लाख रुपए की लागत से नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई।

जिला न्यायालय में जागरूकता कार्यशाला: सुरक्षित कार्यस्थल की दिशा में 'साझा ज़िम्मेदारी' का संदेश

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। एक सुरक्षित कार्यस्थल केवल नियमों से नहीं बनता वह तब बनता है, जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझे और गरिमा, सम्मान तथा समानता को रोज़मर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनाए। इसी सोच के साथ जिला न्यायालय दुर्ग के नवीन सभागार में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा महिलाओं के अधिकार एवं श्रम कानून' विषय पर विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यक्रम का मुख्य संदेश था - Safe Workplace is Everyones Responsibility। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशके. विनोद कुजूर थे। उनके अतिरिक्त कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश सुमन एक्का, विशाखा समिति की अध्यक्ष सुनीता टोप्पो, सदस्यगण, समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता संघ दुर्ग के सदस्य अधिवक्तागण एवं अन्य अधिवक्तागण तथा श्रम विभाग की लेबर इंस्पेक्टर विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इस कार्यशाला की सबसे महत्वपूर्ण बात थी इसका समावेशी दृष्टिकोण। POSH Act को केवल महिलाओं से जुड़ा विषय मानने के बजाय, इस बार न्यायालय के पुरुष अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सक्रिय रूप से सहभागी बनाया गया। महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रथम चरण के बाद यह विशेष सत्र इस विचार पर केंद्रित रहा कि लैंगिक समानता और सुरक्षित कार्यस्थल केवल एक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे संस्थान की साझा ज़िम्मेदारी है।

निगम आयुक्त सुरूसि सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कामर्शियल काम्पलेक्स पार्किंग स्थल, उद्यान, मोबाईल मेडिकल यूनिट, अवैध निर्माण, नाला, सुलभ शौचालय सहित खुर्सीपार स्थित ईएसआईसी डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक सुधार एवं व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

निगम आयुक्त ने नेहरू नगर स्थित कामर्शियल काम्पलेक्स के रिक्त मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने मैदान की साफ-सफाई कराकर व्यवस्थित पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि कामर्शियल काम्पलेक्स में आने वाले नागरिकों को वाहन पार्क करने में सुविधा मिल सके। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर प्रकाश व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने कहा। इसके पश्चात आयुक्त ने बाल क्रीड़ा उद्यान का निरीक्षण किया और स्थानीय नागरिकों से मुलाकात कर उद्यान की व्यवस्थाओं एवं उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। नागरिकों द्वारा बताई गई समस्याओं का निराकरण बरसात के पूर्व कराने के निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार उद्यान में तत्काल अवांछित झाड़ियों की कटाई और ग्रास क्लियर किया गया है। आयुक्त ने मोबाईल मेडिकल यूनिट बस का भी निरीक्षण किया तथा चिकित्सा सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली।

बीएसपी में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने CO2 डैशबोर्ड लॉन्च

■ **डैशबोर्ड संयंत्र और शॉप स्तर पर दैनिक आधार पर कार्बन उत्सर्जन की निगरानी**

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई इस्पात संयंत्र ने अपने डी-कार्बोनाइजेशन प्रयासों को गति देने तथा सतत परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीएसपी एवं चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट , चंद्रपुर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए 'CO2 डैशबोर्ड' का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र द्वारा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का आधिकारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक राकेश कुमार, कार्यपालक निदेशक पी मुरुगेसन, राजीव पांडेय सहित बीएसपी, सीएफपी एवं ईएमडी-कोलकाता के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

यह CO2 डैशबोर्ड पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग द्वारा नियुक्त कंसलटेंट मेसर्स सेंट्रा वर्ल्ड के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य संयंत्र एवं विभिन्न उत्पादन शॉप स्तरों पर होने वाले दैनिक कार्बन उत्सर्जन की सटीक निगरानी और विश्लेषण को सक्षम बनाना है। इस प्रणाली के माध्यम से उत्सर्जन की स्थिति का निरंतर आकलन किया जा सकेगा तथा किसी भी विसंगति की समय रहते पहचान कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में प्रभावी कमी लाई जा सकेगी।

यह डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन पद्धति, जीएचजी प्रोटोकॉल और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्सर्जन का आकलन करने में सक्षम है। भारत में विकसित हो रहे कार्बन बाजार तंत्र और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के परिप्रेक्ष्य में यह डैशबोर्ड सेल को अपने निर्धारित उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्यों को प्राप्त करने और कार्बन बाजार से जुड़ी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयारी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त, उत्पाद एवं शॉप स्तर पर उत्सर्जन की निगरानी से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सेल के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान निदेशक प्रभारी चित्तरंजन महापात्र ने कहा कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना केवल एक नियामकीय बाध्यता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत भविष्य के निर्माण हेतु हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

चिरायु योजना से बाल मधुमेह से जूझ रही 11 वर्षीय बच्ची को मिला निःशुल्क उपचार

रायपुर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की चिरायु योजना ऐसे बच्चों के लिए आशा की किरण बन रही है, जो जन्मजात बीमारियों या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। समय पर पहचान, विशेषज्ञ उपचार और पूरी तरह निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से यह योजना बच्चों को स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर भविष्य देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से समय पर स्वास्थ्य जांच एवं उपचार उपलब्ध होने से न केवल बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर उपचार का बोझ भी कम हो रहा है। मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम नारायणपुर निवासी 11 वर्षीय किनामिका साहू के लिए भी चिरायु योजना ऐसी ही उम्मीद की किरण बनी है। किनामिका बाल मधुमेह से पीड़ित है और उसका उपचार पूर्व में बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था।

जिले में बैंकिंग योजनाओं की कलेक्टर ने की गहन समीक्षा

एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष बैठक में जून 2026 तिमाही के लिए जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बैंकिंग सेवाओं, कृषि एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने, महिला स्व सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के एलडीओ क्षितिज वर्मा, एलडीएम विजन नायक जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, बैंक मैनेजर, डीपीएम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सक्षम कोचिंग की नई कक्षाएं शुरू

सुकमा। जिले के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन सुकमा की अभिनव पहल सक्षम कोचिंग की नई कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। सीजीपीएससी, व्यापमं सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुभवी फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। प्रशासन की इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर एवं दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को भी गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का बेहतर मंच मिल रहा है। सक्षम कोचिंग में युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के साथ पुस्तकालय, हॉस्टल और अध्ययन सामग्री जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले के प्रतिभावान युवाओं को संसाधनों की कमी के कारण अपने लक्ष्य से दूर न होने देना तथा उन्हें निरंतर मार्गदर्शन एवं अध्ययन का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है।

किसानों को इस वर्ष 904 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण : मंत्री कश्यप

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर फसल ऋण समय पर मिलते हैं और किसानों को डिजिटल सेवाएं आसानी से मिलने लगती हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभाकक्ष में बैठक लेकर जिला सहकारी बैंक के कामकाज एवं किसानों के हित में संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

मंत्री केदार कश्यप ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ किसानों को समय पर ऋण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने किसानों के हित में संचालित केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा। सहकारिता मंत्री कश्यप ने बताया कि पांच जिलों में नई 47 सहकारी समितियां खोली गई हैं, जिनमें अकेले बिलासपुर जिले में 16 समितियां शामिल हैं। उन्होंने इन समितियों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित क्षेत्रों के किसानों को स्थानीय स्तर पर सहकारिता से जुड़ी सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नई समितियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधन और सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में किसानों को 73,207.17 लाख रुपये का नगद ऋण तथा 17,273.35 लाख रुपये का वस्तु ऋण वितरित किया गया है। इस प्रकार किसानों को 904 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंत्री श्री कश्यप ने ऋण वितरण की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने तथा सहकारी बैंक की सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। कुछ समितियों में डेटा एंट्री का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस पर मंत्री कश्यप ने 31 अगस्त तक सभी पैक्स में डेटा एंट्री एवं कंप्यूटराइजेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री कश्यप ने 'सहकार से समृद्धि' योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी केंद्रों में आईडी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अन्न भंडारण योजना की भी समीक्षा की गई। योजना का शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गोदाम निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री कश्यप ने अधूरे गोदामों की जानकारी ली। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड एवं संबंधित अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि इनका उपयोग किसानों और सहकारी समितियों के हित में किया जा सके।

मंत्री कश्यप ने किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की समीक्षा करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार और अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए समय पर ऋण सुविधा मिल सके।

उत्कृष्ट शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों से संवर रहा छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य : मुख्यमंत्री

प्रदेश के सभी संभागों की टॉपर बेटियों को किया सम्मानित, प्रदान की स्कॉलरशिप

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। शिक्षा किसी भी समाज और राज्य के विकास का मूल आधार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर देती है और रोजगार उनके सपनों को साकार करने का मजबूत आधार बनता है। छत्तीसगढ़ सरकार उत्कृष्ट शिक्षा, आधुनिक तकनीक और रोजगार के नए अवसरों के माध्यम से प्रदेश के बच्चों और युवाओं का भविष्य संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। गांवों से लेकर सुदूर वनांचलों तक बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की तकनीक के लिए तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के जोरा स्थित एक निजी होटल में आयोजित आईबीसी24 'स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2026' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टॉपर बेटियों को सम्मानित कर उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इन बेटियों की उपलब्धि उनके परिवार और विद्यालय के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर हमारी बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। कार्यक्रम में कक्षा बारहवीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बेमेतरा की ओमनी वर्मा को मुख्यमंत्री श्री साय ने एक लाख रुपए का चेक और सम्मान पत्र प्रदान किया। उनके विद्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम कन्या विद्यालय, बेमेतरा को भी एक लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशिष्टजनों का सम्मान किया तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित पुस्तक 'मेधा' का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिभावान विद्यार्थियों से संवाद करते हुए अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां साझा कीं। उन्होंने कहा कि होनहार बेटियों के बीच आकर उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गृहग्राम बगिया की प्राथमिक शाला में हुई। पांचवीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए उन्हें अपने गांव से कुछ दूर दूसरे गांव जाना पड़ा था। उस समय गांव के स्कूल का भवन मिट्टी का था और उसकी मरम्मत में गांव के लोग मिलकर सहयोग करते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने राज्य निर्माण के 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज प्रदेश में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक संस्थानों का व्यापक नेटवर्क विकसित हुआ है। प्रत्येक विकासखंड में महाविद्यालय उपलब्ध हैं। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान आज छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। इससे प्रदेश के बच्चों को अपने राज्य में ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति की स्थापना के साथ शिक्षा का नया अध्याय भी शुरू हो रहा है। जगरगुंडा और ओरछा जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी की शुरुआत की जा रही है। जिन इलाकों में कभी परिस्थितियों के कारण शिक्षा तक पहुंच चुनौतीपूर्ण थी, वहां अब बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना और अवसर विकसित किए जा रहे हैं।

एआई मिशन से भविष्य की तकनीक के लिए तैयार होगी नई पीढ़ी

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है। राज्य के विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नई तकनीकों से परिचित हों और भविष्य की संभावनाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़ एआई मिशन शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उन्हें भविष्य के रोजगार और नवाचार के अवसरों के लिए तैयार करना है।

जरहाभाठा छात्रावास परिसर : पीपीपी मॉडल पर मल्टी स्टोरी भवन के रूप में होगा विकसित

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आदिम जाति और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बिलासपुर में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य एवं आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ उनके लाभ को अधिक से अधिक किसानों, ग्रामीणों और हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

मंत्री नेताम ने कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं और उनके माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभ की जानकारी केवल कागजों तक सीमित न रहे। योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने के साथ उन्हें योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ और परिणाम भी दिखाया जाए, ताकि अधिक से अधिक किसान इनसे जुड़कर अपनी आय और उत्पादन में वृद्धि कर सकें।

उन्होंने उद्यान विभाग की समीक्षा करते हुए किसानों को अधिकाधिक पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फलदार एवं उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए विभागीय योजनाओं के माध्यम से किसानों को पौधे उपलब्ध कराने तथा रोपण के बाद उनकी देखभाल के लिए आवश्यक मार्गदर्शन देने पर भी जोर दिया।

बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में प्रवेश की स्थिति की भी जानकारी ली गई। मंत्री नेताम ने छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने जरहाभाठा स्थित विभागीय छात्रावास परिसर को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में विकसित करने की जानकारी दी। यह भवन पीपीपी मॉडल के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के लिए बेहतर एवं आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

पीएमएफबीवाय में केसीजी ने रचा नया कीर्तिमान गैर-ऋणी किसानों की भागीदारी में जबरदस्त छलांग

श्रीकंचनपथ न्यूज

जागरूकता कार्यक्रम का असर

जिले में फसल बीमा योजना के प्रति किसानों में बढ़ती जागरूकता से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। फसल बीमा में किसानों की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि किसान अब अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम से सुरक्षित रखने के लिए फसल बीमा को महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में अपना रहे हैं।

रायपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले ने खरीफ2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले वर्ष की तुलना में जिले में फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या के साथ-साथ बीमित क्षेत्रफल में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। विशेष रूप से गैर-ऋणी किसानों की भागीदारी में बड़ी बढ़ोतरी हुई है।

खरीफ2025 में जिले से 11,338 गैर-ऋणी किसान आवेदन प्राप्त हुए थे। खरीफ2026 में यह संख्या बढ़कर 21,186 किसान आवेदन हो गई है। इस प्रकार गैर-ऋणी किसानों की संख्या में 186 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि किसानों में फसल बीमा योजना के प्रति बढ़ते विश्वास और जागरूकता को दर्शाती है। इसी प्रकार गैर-ऋणी किसानों के बीमित क्षेत्रफल में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खरीफ2025 में जहां 2,972 हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा हुआ था, वहीं खरीफ 2026 में यह बढ़कर 5,399 हेक्टेयर हो गया है। इस प्रकार बीमित क्षेत्रफल में लगभग 181 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

फसल बीमा योजना में ऋणी किसानों की भागीदारी भी बढ़ी है। खरीफ2025 में 3,12,493 ऋणी किसान आवेदन प्राप्त हुए थे, जो खरीफ 2026 में बढ़कर 3,15,857 किसान आवेदन हो गए। इसी प्रकार ऋणी किसानों का बीमित क्षेत्रफल 71,874 हेक्टेयर से बढ़कर 72,270 हेक्टेयर हो गया है। ऋणी किसानों की एंट्री अभी जारी है जिसमें बढ़ोत्तरी संभावित है। नुकसान के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिले में किसानों की बढ़ती भागीदारी से कृषि क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और जोखिम-प्रतिरोधी बनाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

बिलासा ताल में बना आकर्षक वुडन ब्रिज, पर्यटन सुविधाओं को मिला नया आयाम

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित कोनी में बने बिलासा ताल में हाल ही में एक आकर्षक नवनिर्मित वुडन ब्रिज (लकड़ी का पुल) से पर्यटन स्थल की सुंदरता और आकर्षण में काफी वृद्धि हुई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने बिलासपुर के बिलासा ताल में 24.38 लाख रुपए की लागत से तैयार वुडन ब्रिज का लोकार्पण किया। प्राकृतिक और मनोरम वातावरण के बीच बनाए गए इस आकर्षक ब्रिज से बिलासा ताल की सुंदरता बढ़ी है। यह ब्रिज पर्यटकों और शहरवासियों के लिए नया आकर्षण बनेगा।

बिलासा ताल के प्राकृतिक परिवेश और पर्यटन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वुडन ब्रिज का निर्माण किया गया है। इसके माध्यम से पर्यटकों को ताल परिसर में घूमने और प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेने के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। ब्रिज के आसपास का क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा।

वुडन ब्रिज के निर्माण से बिलासा ताल की पर्यटन सुविधाओं में एक नया आयाम जुड़ा है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा बढ़ने के साथ पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय नागरिकों के लिए भी यह स्थान मनोरंजन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का बेहतर विकल्प बनेगा। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक सुशांत शुक्ला, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ, पीसीसीएफ अरुण पाण्डेय, सीसीएफ मनोज पांडे, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, वन मंडलाधिकारी नीरज सिंह, नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे, मोहित जायसवाल सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

प्राकृतिक सौंदर्य और विकास का सुंदर संगम

बिलासा ताल में विकसित यह वुडन ब्रिज प्रकृति और पर्यटन विकास के सुंदर समन्वय का उदाहरण है। शासन द्वारा पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और प्राकृतिक स्थलों को आकर्षक बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं और मजबूत हो रही हैं। प्राकृतिक और मनोरम वातावरण के बीच बनाए गए इस आकर्षक ब्रिज से बिलासा ताल की सुंदरता बढ़ी है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया दृश्य संवाद 2026 का शुभारंभ

तस्वीरों में उतरा छत्तीसगढ़, फोटो जर्नलिस्टों का हुआ सम्मान, रायपुर प्रेस क्लब में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फोटो जर्नलिस्ट फेस्ट 'दृश्य संवाद 2026' का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में रायपुर के प्रेस फोटो जर्नलिस्टों के साथ-साथ प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में तस्वीरों के जरिए प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा तथा जनसरोकार से जुड़े विषयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है।

चार कैटेगरी में आयोजित प्रदर्शनी की 'प्रकृति एवं पर्यावरण' कैटेगरी में प्रदर्शित तस्वीरों ने प्रदर्शनी स्थल पर प्राकृतिक सौंदर्य को साकार कर दिया। वहीं 'संस्कृति एवं परंपरा' कैटेगरी की तस्वीरों में छत्तीसगढ़ की लोककला, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की महक महसूस की जा सकती है। 'समाचार एवं जनसरोकार' कैटेगरी में फोटो जर्नलिस्टों की नजर से महत्वपूर्ण घटनाओं और सामाजिक सरोकारों को एक क्लिक में जीवंत रूप दिया गया है।

इस वर्ष रायपुर प्रेस क्लब ने प्रदर्शनी को और व्यापक स्वरूप देते हुए प्रेस क्लब के गैर सदस्य प्रोफेशनल और शौकिया फोटोग्राफरों के लिए भी ओपन कैटेगरी में भागीदारी का अवसर दिया। इस श्रेणी में 35 से अधिक प्रतिभागियों की तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फोटो जर्नलिस्टों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि फोटोग्राफी केवल कैमरे से तस्वीर खींचने का काम नहीं, बल्कि एक पल को इतिहास के लिए सुरक्षित कर देने की कला और जिम्मेदारी है। खासतौर पर फोटो जर्नलिज्म में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं। फोटो जर्नलिस्ट को घटनास्थल पर मौजूद रहकर बेहद कम समय में यह तय करना होता है कि कौन-सा क्षण महत्वपूर्ण है और उसे किस एंगल से कैमरे में कैद किया जाए। उन्होंने कहा कि एक अच्छी तस्वीर के पीछे तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, सही समय की पहचान, सही एंगल और परिस्थितियों को समझने की दृष्टि भी जरूरी है। कई बार पत्रकार घटना को शब्दों में विस्तार से बताते हैं, लेकिन एक तस्वीर वही बात एक क्षण में लोगों तक पहुंचा देती है। यही फोटो जर्नलिज्म की ताकत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब द्वारा विश्व फोटोग्राफी दिवस पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन सराहनीय पहल है। इससे वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्टों के अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचेंगे और युवा तथा शौकिया फोटोग्राफरों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिलेगा। उन्होंने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं दीं। रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी ने सभी फोटो जर्नलिस्टों और फोटोग्राफरों को विश्व फोटोग्राफी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 'दृश्य संवाद' केवल एक फोटो प्रदर्शनी नहीं, बल्कि तस्वीरों के माध्यम से समाज और समय से संवाद करने का प्रयास है।

पहली बार साथ नजर आएंगे कियारा और सैफ अली खान?

कनिका ढिल्लों करेंगी निर्देशन ऐसी होगी फिल्म की कहानी.....

बॉलीवुड फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफअली खान और कियारा आडवाणी पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

कियारा और सैफ अली खान दोनों एक्टर्स इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर व्यस्त हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि दोनों एक इंटेंस थ्रिलर फिल्म में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।

कनिका ढिल्लों करेंगी निर्देशन

खास बात यह है कि इस फिल्म से राइटर-प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू करने जा रही हैं। इस अनटाइटल्ड फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट्स प्रोड्यूस कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसकी स्क्रिप्ट को खास तौर पर सैफ अली खान और कियारा आडवाणी को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है।

सुपरनैचुरल थ्रिलर होगी फिल्म

प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, 'सैफ और कियारा कनिका की अगली फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। यह सुपरनैचुरल एलिमेंट वाली एक इंटेंस थ्रिलर है और इसकी स्क्रिप्ट दोनों एक्टर्स को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। कनिका, एक्सेल एंटरटेनमेंट्स और राइटिंग टीम काफी समय से इस कहानी पर काम कर रही है और अब मेकर्स इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।'

फिलहाल फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार होने के बाद मेकर्स फिल्म से जुड़ी और जानकारी शेयर कर सकते हैं।

'टॉक्सिक' में नजर आएंगी कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी की बात करें तो वह जल्द ही फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आने वाली हैं। फिल्म में यश डबल रोल में दिखाई देंगे।

फिल्म में नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिकाओं में हैं। 'टॉक्सिक' दुनियाभर में 26 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाली है।

'हैवान' में दिखेंगे सैफ अली खान

वहीं सैफ अली खान अगली बार फिल्म 'हैवान' में नजर आएंगे। यह एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसे प्रियदर्शन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। 'हैवान' में सैफ अली खान के साथ अक्षय कुमार, बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी नजर आएंगे। फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा का एक्टिंग डेब्यू

फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में निभाएंगी अहम भूमिका

फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का पहला पोस्टर और टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। इस टीजर में कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा भी नजर आईं। जानिए, वह फिल्म में कौन सा किरदार निभा रही हैं।

इन दिनों राम कथा पर कई फिल्में बन रही हैं। नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस और नितेश तिवारी निर्देशित फिल्म 'रामायण' खूब चर्चा में है। इसी बीच एक और फिल्म राम कथा पर बन रही है। इस फिल्म का नाम 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' है। इस फिल्म के जरिए अंजलि अरोड़ा अपना एक्टिंग डेब्यू भी रही हैं।

कौन बने हैं राम और सीता?

फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के टीजर में राम और सीता विवाह, वनवास यात्रा और रावण की झलक भी मिली है। इस फिल्म में अंजलि अरोड़ा माता सीता के रूप में नजर आएंगी। वहीं देव शर्मा भगवान राम का किरदार निभाएंगे।

कब रिलीज होगी यह फिल्म?

महोबिया फिल्म्स के प्रोडक्शन तले बनी इस फिल्म को प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने प्रोड्यूस किया है। अजय कनौजिया की कंपनी एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ने इसे पेश किया है। इसके डायरेक्टर अभिषेक सिंह हैं। यह फिल्म हिंदी के अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा में भी रिलीज होगी। यह फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'ये कोई स्टंट नहीं था', अनुपमा परमेश्वरन का खुलासा बताया क्यों 'परधा' प्रमोशन के दौरान रो पड़ी थीं एक्ट्रेस

अनुपमा परमेश्वरन फिल्म 'परधा' के प्रमोशन के दौरान रोने लगीं थीं। उस वक्त उन्हें देखकर कई तरह की बातें कही गई थीं। कुछ लोगों ने इसे प्रमोशन का हिस्सा बताया था, तो कुछ ने कहा था कि वह सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हैं।

अनुपमा ने कहा, 'सोचिए, स्टेज पर जाने से पहले आपका अपना बॉयफ्रेंड आपको शर्मिंदा करे। अपनी जिंदगी के दो वर्षों से मैं लगातार यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं ठीक हूं।' अनुपमा ने कहा कि वह जैसी कैमरे के सामने दिखाई देती हैं, असल जिंदगी में भी वैसी ही हैं। वह किसी तरह का दिखावा नहीं करतीं।

उन्होंने कहा, 'आप जिस इंसान से अभी बात कर रहे हैं, मैं हर जगह वही इंसान हूं। मैं कोई मास्क पहनकर घर से बाहर नहीं निकलती। पिछले दो वर्षों से मैं ठीक होने का दिखावा कर रही थी। लेकिन एक बार मैं ऐसा नहीं कर पाई।'

परधा प्रमोशन के दौरान रो पड़ी थीं अनुपमा

अनुपमा ने उस घटना को याद करते हुए बताया कि वह 'परधा' के एक प्रमोशनल इवेंट में लाल चूड़ीदार पहनकर बैठी थीं। इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और वह अचानक रोने लगीं। एक्ट्रेस ने इस घटना पर कहा, 'मैं ऐसी नहीं हूं कि हालात कितने भी मुश्किल हों, स्टेज पर रोने लगूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे वो सबसे बुरी बातें कही गईं, जो कोई महिला सुनना नहीं चाहती। जिस इंसान को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, वही मुझे अंदर से तोड़ रहा था।'

अनुपमा ने बताया कि जब वह प्रमोशनल इवेंट में रोईं तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, 'लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मैं सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही हूं या यह प्रमोशन का हिस्सा है। इसका 'परधा' से कोई लेना-देना नहीं था। यह मेरी असल जिंदगी में जो कुछ चल रहा था, उससे जुड़ा था।'

'धुरंधर' फेम आयशा खान ने पहनी डायमंड रिंग, क्या सच में हो गई सगाई?

'धुरंधर' के गाने 'शरारत' से लोगों का ध्यान खींचने वाली एक्ट्रेस आयशा खान ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस कन्फ्यूज हो गए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।

आयशा खान एक बार फिर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर कुछ खास तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस ने उनकी सगाई की अटकलें लगाना शुरू कर दिया है।

तस्वीरों में आयशा एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आ रही हैं और उनके हाथ में एक खूबसूरत डायमंड रिंग भी दिखाई दे रही है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी सगाई की खबरें तेज हो गई हैं।

हालांकि, तस्वीरों को देखकर भले ही ऐसा लग रहा हो कि आयशा ने सगाई कर ली है, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। आयशा ने इन तस्वीरों में मिस्ट्री मैन का चेहरा छिपा रखा है। वहीं, उनकी पोस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह किसी ज्वेलरी ब्रांड के फोटोशूट का हिस्सा हो सकती है। एक्ट्रेस ने अभी तक अपनी सगाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। आयशा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- 'ए ड्रीम।' अब उनके इस कैप्शन ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तस्वीरों में नजर आ रहा यह मिस्ट्री मैन कौन है और क्या डायमंड रिंग सिर्फ फोटोशूट का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी खबर छिपी है।

'शरारत' गाने से मिली खूब पॉपुलैरिटी

आयशा खान को 'धुरंधर' के सुपरहिट गाने 'शरारत' से काफी लोकप्रियता मिली। फिल्म 'धुरंधर' में 'शरारत' गाने को कराची में होने वाली एक भव्य शादी के बैकग्राउंड में फिल्माया गया है। गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा वेडिंग डांसर्स के रूप में नजर आती हैं। दोनों ने अपने डांस और ग्लैमरस अंदाज से गाने में खूब रंग जमाया है। इस गाने को शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है, जबकि मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस ने इसे अपनी आवाज दी है।

कम हीमोग्लोबिन वालों के लिए वरदान है ये जूस!

अगर आपके शरीर में भी हीमोग्लोबिन कम है, तो अपनी डाइट में ये खास जूस शामिल करें। हीमोग्लोबिन शरीर के अलग-अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसका सामान्य स्तर बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम आया है, तो खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डाइट में आयरन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करने से शरीर को जरूरी पोषण मिल सकता है।

ऐसे में चुकंदर का जूस एक हेल्दी विकल्प हो सकता है। चुकंदर में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसे संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर हीमोग्लोबिन लगातार कम रहता है, तो इसकी वजह जानना और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। साथ ही आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं।

चुकंदर का जूस क्यों है खास?

चुकंदर में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। इसमें मौजूद नाइट्रेट शरीर में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। चुकंदर में फोलेट और कुछ मात्रा में आयरन भी पाया जाता है। हालांकि, सिर्फ चुकंदर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हीमोग्लोबिन कम है, तो आयरन से भरपूर पूरी डाइट लेना जरूरी है।

कैसे बनाएं चुकंदर का जूस?

एक ताजा चुकंदर लें और उसे अच्छी तरह धोकर छील लें। अब इसे छोटे टुकड़ों में काटकर जूसर या ब्लेंडर में डालें। जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी मिलाकर जूस तैयार करें। इसमें स्वाद के लिए नींबू का रस मिलाया जा सकता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी शरीर को पौधों से मिलने वाले आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। जूस में ज्यादा चीनी मिलाने से बचें।

हीमोग्लोबिन के लिए सिर्फ जूस पर निर्भर न रहें

अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, तो केवल चुकंदर का जूस पीना पर्याप्त नहीं है। डाइट में पालक, चना, राजमा, मसूर दाल, बीन्स, तिल और आयरन से भरपूर अन्य खाद्य पदार्थ शामिल करें। इनके साथ आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद जैसे विटामिन सी वाले खाद्य पदार्थ लेने से आयरन के अवशोषण में मदद मिल सकती है। इस दौरान जंक फूड से दूरी बनाना आपके लिए सही माना जाएगा।

चाय-कॉफी का भी रखें ध्यान

आयरन की कमी होने पर खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से बचना बेहतर है। इनमें मौजूद कुछ तत्व आयरन के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए आयरन वाली डाइट और चाय-कॉफी के बीच कुछ अंतर रखना चाहिए।

कब कराएं हीमोग्लोबिन की जांच?

अगर आपको लगातार थकान, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द या थोड़ा काम करने पर सांस फूलने जैसी समस्या रहती है, तो हीमोग्लोबिन की जांच कराना उचित है। अगर रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम आता है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर इसकी वजह पता करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट या अन्य इलाज की सलाह दे सकते हैं।

'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद के बाद अपूर्वा मुखीजा ने क्यों बदला अपना ठिकाना?

अपूर्वा मुखीजा, जिन्हें रेबेल किड के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में बताया है कि वह अब भारत में नहीं रहती हैं। अपूर्वा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वह भारत छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद के बाद की स्थिति के बारे में भी बताया।

क्या बोलीं अपूर्वा?

अपूर्वा ने बताया कि 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। उन्होंने माना कि वह बार-बार शो 'कैंसिल' होने और फिर वापसी करने के सिलसिले से थक चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने व्लॉग्स में कुछ भी बोलने से पहले खुद को फिल्टर करने की कोशिश करती हैं। मगर फिर भी उन्हें समझ नहीं आता कि उन्हें 'कैंसिल' क्यों किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ हफ्तों के लिए भी 'कैंसिल' होने से उनके ब्रांड डील्स पर असर पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि उनकी कमाई रुक जाती है।

न्यूयॉर्क पहुंची अपूर्वा

जब उनसे पूछा गया कि क्या न्यूयॉर्क जाने की कोई खास वजह थी, तो अपूर्वा ने कहा, 'मैंने काफी यात्रा की है और जब मैं न्यूयॉर्क पहुंची तो मुझे लगा 'मैं सच में यहीं रहना चाहती हूं'। इस शहर में कुछ तो बात थी। यह बहुत तेज-तर्रार है, हर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए है, खाना बहुत बढ़िया है। मुझे यहां का आर्किटेक्चर पसंद है और मैंने अपनी पसंदीदा लगभग हर वेब सीरीज में न्यूयॉर्क को देखा है।'

उन्होंने बताया कि चूंकि वह न्यूयॉर्क में रहना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक कॉलेज में अप्लाई किया, और वह न्यूयॉर्क में ही था। उन्होंने कहा, मैंने सोचा अगर मेरा एडमिशन हो जाता है, तो मैं चली जाऊंगी। अपूर्वा की यह हालिया घोषणा अचानक नहीं हुई है। जून 2025 में ही 'रेबेल किड' ने बता दिया था कि वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रही हैं।

क्या था 'इंडियाज गॉट लैटेंट' विवाद?

फरवरी 2025 में, समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में माता-पिता और यौन संबंध के बारे में रणवीर इलाहाबादिया की बातों की काफी आलोचना हुई थी। अपूर्वा भी उस पैनल का हिस्सा थीं और एक कंटेस्टेंट के साथ उनकी बहस की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ अफआईआर भी दर्ज की गईं। बाद में, अपूर्वा ने यह भी बताया कि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिली थीं।

अपूर्वा का वर्कफ्रंट

हाल ही में, अपूर्वा रियलिटी शो 'लॉक अप' में नजर आईं। वह घर के माहौल में बदलाव लाने के लिए दो हफ्ते के लिए एक 'इनफॉर्मेंट' के तौर पर शो में शामिल हुई थीं। शो का समापन श्रेया कालरा की जीत के साथ हुआ।

खास-खबर

शहरी गैस वितरण नीति के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति के तहत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस वितरण को विकसित करने के लिए अधोसंरचना निर्माण के लिए कार्ययोजना के तहत कार्य करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था को प्रभावी रूप से विकसित करने तथा नीति के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पाईप लाईन से प्राकृतिक गैस के घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाएं।

जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक की हुई शुरुआत

दंतेवाड़ा। जिला कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय रामटेके की मार्गदर्शन में तथा यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के तकनीकी सहयोग से जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में अब प्रत्येक बुधवार को टाइप 1 डायबिटीज की शुरुआत की गई है। ज्ञात हो कि जिले में राष्ट्रीय गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों को बेहतर उपचार एवं स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में विशेष टाइप 1 मधुमेह क्लिनिक शुरुआत की गई है यह क्लीनिक प्रत्येक बुधवार को संचालित किया जाएगा जिसके माध्यम से मरीजों को एक ही स्थान पर आवश्यक जांच चिकित्सकीय परामर्श इंसुलिन प्रबंधन पोषण संबंधी मार्गदर्शन और नियमित फॉलो अप की सुविधा मिलेगी।

भखारा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन का समय निर्धारित

धमतरी। जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आम नागरिकों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धमतरी से भखारा होकर जाने वाले भारी वाहनों के आवागमन का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार सुबह 6.00 बजे से रात 10.00 बजे तक भारी वाहनों का इस मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। रायपुर से भखारा, धमतरी होकर अन्य स्थानों एवं शहरों की ओर जाने वाले भारी वाहनों को निर्धारित समयावधि में भखारा मार्ग का उपयोग नहीं करना होगा। ऐसे भारी वाहन अपने गंतव्य तक आवागमन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करेंगे। इससे भखारा मार्ग पर यातायात का दबाव कम होने के साथ स्थानीय नागरिकों एवं छोटे वाहनों के लिए आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम होगा।

नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगाः मुख्यमंत्री साय

श्रीकंचनपथ न्यूज

मुख्यमंत्री ने 'स्रोत महोत्सव 2026' एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

रायपुर। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, कृषि और समृद्धि की जीवनधारा हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाने में प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिन नदियों ने हमारी सभ्यता को पोषित किया और हमें समृद्धि दी, उनका संरक्षण हम सभी का साझा दायित्व है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के ओमाया गार्डन में आयोजित 'स्रोत महोत्सव 2026' एवं राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रदेश की नदियों के उद्गम स्थलों एवं जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण, जल संचयन एवं भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने तथा नदी संरक्षण को व्यापक जन अभियान का स्वरूप देना है। कार्यशाला में जल संरक्षण, नदी पुनरुद्धार और जल प्रबंधन से जुड़े विषय विशेषज्ञों के साथ राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों के सदस्य तथा विभिन्न जिलों के प्रतिनिधियों द्वारा मंथन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नदी बचेगी तो जल बचेगा और जल बचेगा तो जीवन बचेगा। इसी भावना के साथ राज्य सरकार नदियों के उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक तकनीक, पारंपरिक ज्ञान और जनभागीदारी के समन्वय से व्यापक कार्ययोजना पर आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान नदियों से गहराई से जुड़ी हुई है। महानदी सहित प्रदेश की अनेक नदियों ने कृषि, आजीविका और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया है। नदियों का अस्तित्व उनके उद्गम स्थलों और कैचमेंट एरिया के स्वास्थ्य पर निर्भर है। इसलिए नदी संरक्षण का कार्य केवल उसके प्रवाह क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकता। हमें नदी के स्रोत से लेकर उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समझकर संरक्षण की समग्र योजना बनानी होगी।

उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। स्रोत महोत्सव में विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवों के आधार पर ऐसी ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसे धरातल पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संरक्षण का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। नदियों के किनारे बसे गांवों और वहां रहने वाले लोगों का नदी से सीधा संबंध है, इसलिए उन्हें नदी संरक्षण की प्रक्रिया का प्रमुख भागीदार बनाना होगा।

पांच प्रमुख स्तंभों पर आगे बढ़ेगा नदी संरक्षण अभियान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में नदी संरक्षण के लिए मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जनभागीदारी और कार्ययोजना के पांच प्रमुख स्तंभों पर काम किया जाएगा। प्रत्येक नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र का वैज्ञानिक तरीके से मानचित्रण किया जाएगा। नदी का उद्गम कहां है, उसके प्रवाह क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, भू-उपयोग में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं और किन कारणों से नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है - इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक मानचित्रण और अध्ययन के आधार पर नदी के पूरे इकोसिस्टम के संरक्षण की योजना तैयार की जाएगी। इसमें वन एवं वनस्पति संरक्षण, मृदा क्षरण की रोकथाम, पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, आवश्यकतानुसार नई जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण और भू-जल पुनर्भरण जैसे कार्य शामिल होंगे।

श्रमिक परिवारों को मिले शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवायसी प्रक्रिया के तहत किसी भी श्रमिक का आवेदन लंबित न रहे और सभी पात्र श्रमिकों को शासन की योजनाओं का समय पर लाभ मिले।

मंत्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्य में संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करें। श्रम मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चार नए श्रम संहिताएं बनाई गई हैं। सभी श्रम अधिकारी इन कानूनों का अध्ययन कर लें।

उन्होंने कहा कि नए जिलों के श्रम कार्यालयों में जल्द ही सेटअप अनुसार अधोसंरचना का विस्तार किया जाएगा। बैठक में उन्होंने श्रमिकों के पंजीयन के लिए प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। ठेकेदार को जितने श्रमिकों का लाइसेंस प्राप्त है, उतने ही श्रमिक कार्यरत हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने तथा कारखानों की नियमित जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। बैठक में ऑनलाईन रेण्डम निरीक्षण, अभियोजन एवं निराकरण की कार्यवाही, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम अंतर्गत पंजीयन की समीक्षा सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें मिनी माता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना, असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति योजना, ई-रिक्शा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, असंगठित कर्मकार महतारी जतन योजना और बस्तर मुन्ने पोर्टल (नियद नेल्ला नार 2.0) शामिल हैं। सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिमशिखर गुप्ता ने जिलों के श्रम पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि इस योजना में अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलता है अथवा किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो संबंधित जिलों के श्रम अधिकारी जवाबदेह होंगे और उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

सचिव गुप्ता ने बताया कि 24 अगस्त मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में राजधानी रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के अंतर्गत सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर चालू शैक्षणिक सत्र से इस योजना में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 की गई है। इसके तहत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

सिंधी सेवा महिला विंग ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू से की सौजन्य मुलाकात

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू से छत्तीसगढ़ सिंधी सेवा महिला विंग के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. ममता साहू को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुलाकात के दौरान महिला विंग की प्रतिनिधियों ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में राज्य महिला आयोग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। इस अवसर पर भावना कुकरेजा, साधना गुरनानी, कुसुम डोडवानी, कुसुम, अनीता, हेमा, पाखी, मंजू एवं ज्योति सहित सिंधी समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं।

बारिश के बीच खेतों में पहुंचा कृषि अमला, जवाफुल धान की जैविक खेती और सन बीज उत्पादन पर जोर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायगढ़ जिले के लैलूंगा क्षेत्र में कृषि गतिविधियों और किसानों को मिल रहे योजनागत लाभों की जमीनी स्थिति जानने के लिए आज संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर आर.के.राठौर एवं उपसंचालक कृषि अनिल वर्मा ने संयुक्त भ्रमण किया। कृषि अधिकारियों ने किसानों के खेतों तक पहुंचकर फसल स्थिति का जायजा लिया और उन्नत एवं जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

भ्रमण की शुरुआत वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय लैलूंगा में कृषि विभाग के मैदानी अमले की बैठक से हुई। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टैक, फसल स्थिति एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। संयुक्त संचालक श्री राठौर ने योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा पात्र किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक के बाद बारिश के बीच कृषि अधिकारियों ने किसानों के खेतों का भ्रमण किया। इस दौरान लैलूंगा क्षेत्र में की जा रही सुगंधित जवाफुल धान की तकनीकी खेती का अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने किसानों द्वारा अपनाई जा रही जैविक कृषि पद्धतियों, जीवामृत एवं हरी खाद के उपयोग की जानकारी ली और इन प्रयासों की सराहना की। श्री राठौर ने कहा कि लैलूंगा का जवाफुल धान अपनी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के कारण अलग पहचान रखता है।

सेवा सेतु ने बदली सरकारी सेवाओं तक पहुंच की तस्वीर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में सेवा सेतु केंद्र नागरिकों के लिए शासकीय सेवाओं को सरल, सहज और सुगम बनाने की दिशा में प्रभावी माध्यम बन रहा है। एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन की सुविधा और निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं की उपलब्धता से नागरिकों को अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने में सुविधा मिल रही है।

इसके माध्यम से जाति, निवास एवं आय प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ नागरिकों को समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल शासन की सेवाओं को नागरिकों के करीब लाने के साथ ही उनके समय और प्रयास की बचत में सहायक बन रही है। सेवा सेतु की सफलता उन नागरिकों के अनुभवों में भी दिखाई दे रही है, जिन्हें आवश्यक दस्तावेज समय पर प्राप्त हो रहे हैं और उनके कार्य आसानी से पूरे हो रहे हैं। इसी क्रम में कोरबा जिले के ग्राम ढेंगूरडीह, तहसील भैंसमा निवासी जग्गू राठिया के लिए अपने बच्चों उमा और हेमलता से जुड़े जरूरी कार्यों के लिए जाति, निवास एवं आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता थी। बच्चों के आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए इन प्रमाण-पत्रों की जरूरत को देखते हुए श्री राठिया ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवा सेतु केंद्र का रुख किया। उन्होंने केंद्र में पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया।

सेवा सेतु केंद्र में आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई। आवेदन के निराकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करते हुए श्री राठिया के बच्चों उमा और हेमलता के जाति, निवास एवं आय प्रमाण-पत्र समय-सीमा के भीतर तैयार कर उपलब्ध कराए गए। समय पर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से राठिया को अपने बच्चों से संबंधित आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाने में सुविधा मिली। प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद जग्गू राठिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु केंद्र में आवेदन करने के बाद उनका काम समय पर पूरा हो गया।

लोक निर्माण से छत्तीसगढ़ निर्माण के मूलमंत्र के साथ अधोसंरचना विकास को दे रहे नई गति- अरुण साव

पिछले ढाई सालों में 12,666 करोड़ के 1572 कार्यों को मिली प्रशासकीय स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में लोक निर्माण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य का सबसे बड़ा निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ के विकास का आधार है।

सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण के साथ विभागीय कार्यों में तेजी और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए विभाग लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर-2023 में सरकार बनने के बाद से अब तक लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी और अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव भी प्रेस-कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने प्रेस-कान्फ्रेंस में बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग को 12 हजार 666 करोड़ रुपए से अधिक के लागत के कुल 1572 कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृतियां मिली हैं। इसमें सड़क निर्माण के 1285, पुलों के 247 और भवन निर्माण के 42 कार्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसम्बर-2023 से मार्च-2024 तक 80 कार्यों के लिए 551 करोड़ 42 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 374 किमी लंबाई की 72 सड़कें, 6 पुल और दो भवन शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2590 करोड़ 70 लाख रुपए लागत के कुल 438 कार्यों के लिए की स्वीकृति दी गई। इनमें 1465 किमी लंबाई की 400 सड़कें, 37 पुल और एक भवन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 लोक निर्माण विभाग के लिए ऐतिहासिक रहा। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इस वर्ष 9129 करोड़ 18 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली, जो राज्य निर्माण के बाद पिछले 25 वर्षों के इतिहास में विभाग को मिली सर्वाधिक स्वीकृति है। इस वित्तीय वर्ष में 5129.60 किमी लंबाई की 754 सड़कों, 200 पुलों और 39 भवनों सहित कुल 993 कार्यों को मंजूरी दी गई। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक विभाग को 608 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें 608.20 किमी लंबाई की 59 सड़कें और दो पुलों के निर्माण शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में विभाग में कार्यों की गति बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया गया है। बेहतर संचालन और प्रशासनिक कसावट के लिए सात नए संभागीय कार्यालय और 12 नए उप संभागीय कार्यालय शुरू किए गए हैं। इससे निर्माण कार्यों की निगरानी और स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि विभाग की प्राथमिकताओं में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण भी शामिल है।

श्री साव ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए जल्द ही 'वमिस' **(WAMIS - Work and Accounts Monitoring Integration System)** लागू किया जाएगा। इस प्रणाली से डीपीआर तैयार करने से लेकर कार्य की स्वीकृति और अन्य प्रक्रियाएं ऑनलाइन और एकीकृत प्रणाली से संचालित होंगी। इससे वर्तमान में विभागीय प्रक्रियाओं में लगने वाले लंबे समय को कम किया जा सकेगा और निर्माण कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारा जा सकेगा।

सरस्वती शिशु मंदिर में डिजिटल-एआई स्मार्ट कक्षाओं का शुभारंभ

सुकमा। आदिवासी बाहुल्य सुकमा जिले में शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत हुई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर सुकमा में डिजिटल एंड्रॉयड एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आधारित स्मार्ट कक्षाओं का भव्य शुभारंभ राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस पहल से अब वनांचल के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, ऑडियो-वीडियो माध्यम और इंटरैक्टिव शिक्षण के जरिए महानगरों जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा। सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय की इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए अधोसंरचना विकास के लिए 5 लाख रुपये की घोषणा की।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

ॐ SAIRAM Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

भारत माला रोड पर 11 बछड़ों की तस्करी का मामला, दो आरोपी गिरफ्तार

कांकेर। गौवंश तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी दुधावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 बछड़ों को कथित रूप से क्रूरतापूर्वक पिकअप वाहन में भरकर ले जाने के मामले में दो आरोपियों झमेश्वर साहू, ताराचंद साहू, को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पिकअप, 11 गौवंश एवं मोबाइल फोन जब्त किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कांकेर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि पशु तस्करी अथवा किसी अन्य अवैध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। किसी संदिग्ध व्यक्ति या आपराधिक गतिविधि की सूचना जिला उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस के अपराध हेल्पलाइन नंबर 94791-55125 पर दी जा सकती है। पुलिस के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

रेलवे ट्रैक पर रखा 7 फीट लंबा लोहे का पाइप, मालगाड़ी के गुजरने के बाद मचा हड़कंप

रायपुर। गोंदवारा ओवरब्रिज और अंडरब्रिज के बीच रेलवे ट्रैक पर लोहे का पाइप रखकर रेल परिचालन को बाधित करने की कोशिश का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने रेलवे पटरी पर करीब 1.5 इंच मोटा और 7 फीट लंबा लोहे का पाइप रख दिया था। इसी दौरान वहां से एक मालगाड़ी गुजर रही थी। ट्रैक पर पाइप पड़ा होने के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। रेलवे ट्रैक पर इस तरह बाधा उत्पन्न करने की घटना को गंभीर मानते हुए जीआरपी थाना रायपुर ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153, 174(सी) और 147 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच कर रही है।

भिलाई सिसकोल प्लांट में हादसा, लोहे की प्लेट गिरने से मजदूर की मौत

भिलाई। भिलाई के हथखोज औद्योगिक क्षेत्र स्थित सिसकोल प्लांट में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। क्रेन से लोहे की प्लेट गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान धमधा निवासी राजेश निर्लमलकर (40) के रूप में हुई है। राजेश धमधा से भिलाई आकर प्लांट में काम करता था। राजेश प्लांट में क्रेन ऑपरेट कर रहा था। इसी दौरान क्रेन से लोहे की प्लेट उठाकर ले जाई जा रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ने से प्लेट क्रेन से फिसलकर नीचे गिर गई। प्लेट सीधे राजेश के ऊपर जा गिरी। हादसे में राजेश को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिसकोल प्लांट में इस तरह का हादसा पहले भी हो चुका है। करीब 7 महीने पहले क्रेन से लोहे की प्लेट गिरने से एक मजदूर की मौत हुई थी। उस हादसे में लेखूराम कौशल की जान गई थी। काम के दौरान क्रेन से लोहे की प्लेट फिसलकर उसके ऊपर गिर गई थी।

3 युवकों से 86 हजार की ठगी: लोन कंपनी का एजेंट बनकर मांग रहे बैंक डिटेल-पासवर्ड

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायपुर में साइबर ठग अब लोन देने वाली कंपनियों के एजेंट बनकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। आरोपी फोन और वॉट्सऐप के जरिए लोगों से संपर्क कर खुद को लोन कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। इसके बाद बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड और लोन से जुड़ी रकम के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है।

मोवा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां निजी लोन कंपनी के तीन ग्राहकों से कुल 86 हजार 800 रुपए की ठगी की गई। मामला मोवा स्थित क्रेडिट सी लोन मेघदूत मर्केनटाइल प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है। कंपनी के कर्मचारी प्रद्युमन लिमसाखरे ने मामले की शिकायत पुलिस से की है।

कंपनी ने तीन ग्राहकों को अलग-अलग लोन दिया था। इसके बाद अज्ञात आरोपियों ने ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर फोन और वॉट्सऐप के जरिए संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को क्रेडिट सी

लोन कंपनी का कर्मचारी बताया। लोन से जुड़ी जानकारी देकर उन्होंने ग्राहकों का भरोसा जीता। इसके बाद बैंक खाते की डिटेल और अन्य निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। आरोप है कि आरोपियों ने लोन की रकम से जुड़े लेनदेन का हवाला देकर ग्राहकों से अपने बताए बैंक खातों में कुल 86,800 रुपए जमा करा लिए। रकम मिलने के बाद आरोपियों ने ग्राहकों से संपर्क करना बंद कर दिया।

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। लोन, किस्त या भुगतान के नाम पर फोन करने वाले अनजान लोगों के साथ बैंक डिटेल, पासवर्ड, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी भी तरह का भुगतान करने से पहले संबंधित कंपनी के अधिकृत नंबर पर संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करें। अनजान लोगों के बताए खातों में पैसे जमा करने से भी बचें।

फर्जी सिम बेचने वालों पर होगी एफआईआर

रोजाना साइबर पोर्टल लॉगिन के निर्देश, बैंकों में होल्ड ठगी की रकम जल्द लौटाने पर दिया जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। बिलासपुर रेंज में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर रोक लगाने और पीड़ितों को जल्द राहत दिलाने के लिए आईजी राम गोपाल गर्ग ने विशेष समीक्षा बैठक ली। इसमें रेंज के साइबर थानों, साइबर सेल और संबंधित अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में लंबित शिकायतों, एफआईआर, बैंक में होल्ड राशि और साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे डिजिटल संसाधनों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

आईजी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। फर्जी या संदिग्ध सिम सक्रिय करने और बेचने वाले पीओएस एजेंटों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही रेंज के सभी सामान्य थानों को नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर रोज लॉगिन करने को कहा गया। पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों को उसी दिन स्वीकार कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस मुख्यालय से बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर जिलों के संदिग्ध म्यूल अकाउंट की सूची भी भेजी गई है। आईजी ने इन खातों पर तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

सिर्फसाइबर थाना नहीं, हर थाने को रोजाना करना होगा लॉगिन

आईजी ने निर्देश दिया कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर केवल साइबर थाने ही नहीं, बल्कि रेंज के सभी सामान्य थाने भी रोजाना लॉगिन करेंगे। पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को उसी दिन स्वीकार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने और शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने पर विशेष जोर दिया गया।

बैंक में होल्ड पैसा पीड़ितों को लौटाने में तेजी

साइबर ठगी के मामलों में सबसे महत्वपूर्ण राहत के रूप में पीड़ितों की रोकी गई राशि जल्द वापस कराने पर भी आईजी ने जोर दिया। बैंकों में होल्ड की गई रकम को पीड़ित के खाते में वापस कराने के लिए धारा 106 और न्यायालयीन आदेश की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से 15 दिन से अधिक पुराने बैंक होल्ड मामलों की तत्काल समीक्षा कर राशि जल्द से जल्द पीड़ितों को वापस कराने को कहा गया।

ठगी में इस्तेमाल नंबर और डिजिटल अकाउंट होंगे ब्लॉक

साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, वाट्सऐप और टेलीग्राम अकाउंट को प्राथमिकता के आधार पर ब्लॉक कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसकी प्रगति की मासिक रिपोर्ट उच्च कार्यालय को भेजी जाएगी। आईजी ने कहा कि साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल माध्यमों पर समय रहते कार्रवाई करने से आगे होने वाली ठगी को रोका जा सकता है।

समन्वय पोर्टल पर पूरा ब्योरा होगा अपलोड

साइबर ठगी में गिरफ्तार आरोपियों का पूरा ब्योरा, फिंगरप्रिंट और केस का स्टेटस समन्वय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। युवाओं को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने के लिए पंजीकृत वालंटियर्स का सत्यापन भी जल्द पूरा किया जाएगा। रामगोपाल गर्ग ने कहा कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पुलिस कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना है। सभी अधिकारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें, ताकि जनता को इसका सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।

खाद-कीटनाशक दुकानों पर कृषि विभाग की सख्ती एक लाइसेंस निलंबित और दो पर बिक्री प्रतिबंध

श्रीकंचनपथ समाचार

धमतरी। जिले के सहकारी संस्थानों एवं निजी उर्वरक-कीटनाशक विक्रय परिसरों का नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।

धमतरी जिले में किसानों को खाद और कीटनाशक सही कीमत पर मिले और बाजार में कालाबाजारी पर रोक लगे, इसके लिए कृषि विभाग ने जिलेभर में निगरानी तेज कर दी है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर विभाग की टीम सहकारी समितियों के साथ-साथ निजी खाद-कीटनाशक दुकानों का लगातार निरीक्षण कर रही है। जांच के दौरान गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

इसी अभियान के तहत जिले के अलग-अलग विकासखंडों में कई दुकानों और सहकारी संस्थानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान मेसर्स मधु कृषि केन्द्र, कोलियारी में अनियमितता पाए जाने पर उप संचालक कृषि ने उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं मेसर्स गंगबेर कृषि केन्द्र, अछोटा और मेसर्स शिवम ट्रेडर्स, खरेंगा के खिलाफ बिक्री प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आठ अन्य कृषि केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर निर्धारित समय में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि विभाग ने साफ किया है कि खाद और कीटनाशक की उपलब्धता, स्टॉक, गुणवत्ता और निर्धारित बिक्री दर पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसानों को अधिक कीमत पर सामग्री बेचने, बिना बिल खाद-कीटनाशक देने, स्टॉक में गड़बड़ी करने या गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत मिलने पर विक्रेताओं के खिलाफकड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर लाइसेंस निलंबित या निरस्त भी किया जा सकता है। विभाग ने किसानों से कहा है कि खाद और कीटनाशक केवल सहकारी समितियों या अधिकृत निजी दुकानों से ही खरीदें। खरीदारी के समय निर्धारित कीमत की जांच करें और हर सामान का पक्का बिल जरूर लें। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई: 3.712 किलो गांजा और 30 पौव्वा शराब जब्त, 4 गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पुरानी भिलाई, नेवई और धमधा थाना क्षेत्र में की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 3.712 किलो गांजा, 30 पौव्वा देशी शराब, दो दोपहिया वाहन, मोबाइल फोन और नकद राशि जब्त की है।

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुरानी भिलाई पुलिस को 18 अगस्त को सूचना मिली थी कि हथखोज के बंधवा तालाब के पास दो लोग एक्टिवा से गांजा बेच रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और एक्टिवा पर सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया।

पुलिस ने आरोपियों की पहचान खुर्सीपार उड़िया मोहल्ला निवासी दिनेश उर्फ दिनू पाल (47) और दीनदयाल उपाध्याय नगर, चरोदा निवासी चंदन झा (43) के रूप में की। तलाशी में उनके पास से 2.430 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब

1.25 लाख रुपए बताई गई है।

इसके अलावा एक्टिवा, दो मोबाइल फोन और 1,100 रुपए नकद जब्त किए गए। कुल जब्ती की कीमत करीब 1.65 लाख रुपए है। पुरानी भिलाई थाने में अपराध क्रमांक 438/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 27(ए) में मामला दर्ज किया गया है।

नेवई पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक से नेवई डैम के आसपास घूमकर गांजा बेच रहा है। पुलिस ने नाली किनारे, नेवई बस्ती के पास घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान खरीत हरणा उर्फ राहुल (25), निवासी उत्कल नगर, पद्मनाभपुर के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से 1.282 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 63 हजार रुपए है। पुलिस ने बिना नंबर की स्प्लेंडर प्लस बाइक और 250 रुपए नकद भी जब्त किए। कुल जब्ती की कीमत 73,250 रुपए बताई गई है। नेवई थाने में अपराध क्रमांक 555/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 27(ए) में मामला दर्ज किया गया है।

धमधा पुलिस ने ग्राम करेली के पथर्रा खार में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस बोर मशीन भवन के पास पहुंची और घेराबंदी कर एक युवक को पकड़ा।

पूछताछ में उसकी पहचान संजय सिवारे (30), निवासी ग्राम करेली, वार्ड नंबर 9 के रूप में हुई। तलाशी में सफेद-लाल झोले के अंदर रखी सफेद बोरी से 30 पौव्वा देशी प्लेन शराब मिली। इसकी कीमत करीब 2,400 रुपए है। पुलिस ने बिक्री के 480 रुपए भी जब्त किए। कुल जब्ती 2,880 रुपए की हुई।

शराब दुकान के बाहर युवक से मारपीट, इलाज के दौरान मौत, विवाद के बाद नर्सरी ले गया था युवक

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। दुर्ग जिले के पाटन में बुधवार को शराब दुकान के सामने युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय रुपेश वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई। रुपेश ग्राम फुंडा का रहने वाला था और पाटन शराब दुकान के अहाते में काम करता था।

जानकारी के अनुसार, रुपेश शराब दुकान के अहाते में काम कर रहा था। इसी दौरान एक युवक अपने पिता के साथ शराब दुकान पहुंचा। किसी बात को लेकर उसका रुपेश से विवाद हो गया। आरोप है कि युवक रुपेश को शराब दुकान के पास स्थित नर्सरी

की ओर ले गया और वहां करीब आधे घंटे तक उसके साथ मारपीट की।

सिर, सीने और गुप्तांग में लगी चोट

मारपीट में रुपेश के सिर, सीने और गुप्तांग में गंभीर चोटें आईं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने मारपीट रोकने की कोशिश की थी या नहीं। पाटन थाना प्रभारी के मुताबिक, घटना की सूचना मिलने पर 112 की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घायल रुपेश को पाटन अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे घर ले गए। कुछ समय बाद रुपेश की तबीयत फिर बिगड़ गई। परिजन उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

चीचा निवासी युवक पर संदेह

पुलिस के अनुसार, मारपीट करने वाले संदिग्ध युवक को ग्राम चीचा का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उसके नशे का आदी होने की बात कही है। घटना के समय भी उसके नशे में होने की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। थाना प्रभारी ने बताया कि 112 की टीम संदिग्ध युवक को पाटन थाने लेकर पहुंची है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तेज रफ्तार कार ने मोपेड को मारी टक्कर पिता-पुत्री में बेटी की मौत; चालक फरार

कवर्धा। जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोपेड सवार युवती की मौत हो गई, जबकि उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा मुंगेली-पंडरिया मार्ग पर डोमसरा गांव के पास बिजली ऑफिस के सामने हुआ। घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

डोमसरा निवासी 35 वर्षीय फुलेश्वरी निर्मलकर अपने पिता के साथ खेत से काम करके मोपेड से घर लौट रही थीं। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोपेड को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फुलेश्वरी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही कुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पिता को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद कार चालक वाहन को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालक की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

परछी में छिपाकर रखा हुआ गांजा जब्त, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। पुसौर पुलिस ने ग्राम पुटकापुरी में कार्रवाई करते हुए घर के बाहर परछी में छिपाकर रखा गांजा बरामद किया है। आरोपी के कब्जे से गांजा बरामद होने के बाद उसके खिलाफ थाना पुसौर में धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ग्राम पुटकापुरी में एक व्यक्ति घर के बाहर परछी में खाद की बोरी के पीछे गांजा छिपाकर रखा है। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति परछी में छिपने का प्रयास कर रहा था, जिसे टीम ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम भुरवा दास महंत निवासी ग्राम पुटकापुरी बताया। खाद की बोरी के पीछे प्लास्टिक झिल्ली में लिपटा गांजा मिला। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत करीब 8 हजार रुपए बताई गई है।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) संभाग दुर्ग (छ.ग.)

// निविदा आमंत्रण सूचना //

ज्ञाप क्र. 4839 /नि.प्र. क्र.–08/लो.नि.वि./2026-27 दुर्ग, दिनांक 17/08/2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य का विद्युतीकरण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 31/08/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक

ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 08/09/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि :- 09/09/2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि में अवकाश हो या अधोहस्ताक्षरकर्ता शासकीय दौरे पर हो तो निविदा आगामी कार्य दिवस मे खोली जावेगी।

स.क्र./ निविदा क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1	2	3
(1) T0075	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Durg	9.50 Lacs
(2) T0076	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Non Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Durg	9.00 Lacs
(3) T0077	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Balod	9.15 Lacs
(4) T0078	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Non Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Balod	9.71 Lacs
(5) T0079	Providing E/F work for Ordinary Maintenance to Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Mohla-Manpur-Ambagarhchowki	7.80 Lacs
(6) T0080	Providing E/F work for Ordinary Maintenance to Non Residential Buildings under PWD (E/M) Sub Dn., Mohla-Manpur-Ambagarhchowki	9.00 Lacs
(7) T0081	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Bemetara	10.00 Lacs
(8) T0082	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Non Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Bemetara	9.00 Lacs
(9) T0083	Providing E/F work for Ordinary Maintenance to Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai	6.00 Lacs
(10) T0084	Providing E/F work for Ordinary Maintenance to Non Residential Buildings under PWD (E/M) Sub Dn., Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai	6.50 Lacs
(11) T0085	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Kawardha	9.74 Lacs
(12) T0086	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Non Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Kawardha	8.78 Lacs
(13) T0087	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Rajnandgaon	8.00 Lacs
(14) T0088	Providing Electrification work for Ordinary Maintenance to Non Residential Buildings under P.W.D. (E/M) Sub Division, Rajnandgaon	6.10 Lacs

निविदा संबंधी शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र मे उपलब्ध है। निविदा संबंधी अन्य शर्तें का अवलोकन संभागीय कार्यालय में किया जा सकता है।

टीप:- (1) आबंटन प्राप्त होने पर ही देयक का भुगतान किया जायेगा।

जी- 262702848/6

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (वि./यां.) संभाग दुर्ग

खेलो छत्तीसगढ़ • बढ़ो छत्तीसगढ़

खेलों से बदलती तस्वीर

नया छत्तीसगढ़, नए अवसर और नई पहचान

— खेल मैदानों से निकल रही नई ऊर्जा, युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान —

छत्तीसगढ़ आज केवल अपनी प्राकृतिक संपदा, संस्कृति और परंपराओं के लिए ही नहीं, बल्कि खेलों के क्षेत्र में उभरती नई पहचान के लिए भी देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं ने खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाकर हजारों युवाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। खेल अब केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह आत्मविश्वास, रोजगार, सामाजिक परिवर्तन और प्रदेश की नई पहचान का आधार बन चुका है। राज्य के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों से लेकर शहरों तक खेलों का ऐसा वातावरण निर्मित हुआ है, जहां प्रतिभाओं को अवसर मिल रहे हैं और युवाओं के सपनों को पंख लग रहे हैं। खेल अवसंरचना का विस्तार, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं, खेल अकादमियों की स्थापना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों का संरक्षण—इन सभी प्रयासों ने छत्तीसगढ़ को खेल विकास के एक नए मॉडल के रूप में स्थापित किया है।

मुख्यमंत्री का संदेश

“ हमारी सरकार का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ का प्रत्येक युवा अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर प्राप्त करे। खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त आधार है। इसी सोच के साथ हम गांवों, वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों तक खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। बस्तर ओलंपिक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, खेल अकादमियों और युवा कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों युवाओं को नई दिशा मिली है। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ”

-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

बस्तर बना खेल क्रांति का नया केंद्र

कभी चुनौतियों और संघर्षों के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर आज खेल प्रतिभाओं की नई धरती के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित बस्तर ओलंपिक ने इस परिवर्तन को नई दिशा दी है। गांव-गांव और जंगलों के बीच बसे इलाकों से हजारों युवा खेल मैदानों तक पहुंचे हैं। खेलों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक मंच मिला है और उनके भीतर छिपी प्रतिभाओं को पहचान मिली है। फुटबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और अन्य खेलों में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर यह साबित किया है कि अवसर मिलने पर बस्तर की प्रतिभाएं किसी से कम नहीं हैं। इस पहल ने सामाजिक समरसता को भी मजबूत किया है।

आधुनिक खेल अकादमियां गढ़ रहीं भविष्य के चैंपियन

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आधुनिक खेल अकादमियों का नेटवर्क लगातार मजबूत किया गया है। बस्तर क्षेत्र में शुरू हुई आवासीय खेल अकादमी ने आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इन अकादमियों में खिलाड़ियों को आवास, भोजन, खेल सामग्री, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अनुभवी प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। तीरंदाजी, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी और अन्य खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं।

सरगुजा ओलंपिक : खेल प्रतिभाओं को उड़ान देने का छत्तीसगढ़ मॉडल

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित सरगुजा ओलंपिक 2025-26 युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कराटे और तीरंदाजी सहित 12 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी विकासखंड, जिला एवं संभाग स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन व्यवस्था से अधिकाधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र, शील्ड, मोमेंटो और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। यह आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को मंच देने का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

खिलाड़ियों के सम्मान में खुला प्रोत्साहन का नया अध्याय

राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए देश की अग्रणी पुरस्कार नीतियों में से एक को लागू किया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिलने से खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ा है। अब खेल को केवल शौक नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक करियर के रूप में भी देखा जाने लगा है। हजारों युवा खेलों के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।

सामाजिक समरसता को मिली नई मजबूती

खेलों के जरिए सशक्त हो रहा नया छत्तीसगढ़

आज छत्तीसगढ़ में खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, युवा सशक्तीकरण और समावेशी विकास का प्रभावी साधन बन चुका है। खेल मैदानों में दौड़ते युवा, तीरंदाजी के लक्ष्य भेदते खिलाड़ी, हॉकी और फुटबॉल के उभरते सितारे तथा पारंपरिक खेलों में भाग लेते ग्रामीण जन—ये सभी एक विकसित और आत्मविश्वासी छत्तीसगढ़ की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। राज्य सरकार की खेलोन्मुखी नीतियों और निरंतर प्रयासों ने प्रदेश को नई पहचान दी है। आने वाले वर्षों में यही युवा शक्ति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर और अधिक मजबूत स्थान दिलाएगी।

मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्टता मिशन से नई संभावनाएं

प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को प्रारंभिक स्तर से पहचानकर उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कृष्टता मिशन एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आया है। इस मिशन के अंतर्गत खेल अवसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं, कोचिंग व्यवस्था और प्रतियोगिताओं के आयोजन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है।

राष्ट्रीय मंच पर चमक रही छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं

आज छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रदेश के युवा धावकों, तीरंदाजों, हॉकी खिलाड़ियों और अन्य खेल प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों से निकलकर राष्ट्रीय टीमों तक पहुंचने वाले खिलाड़ियों की सफलता यह दर्शाती है कि सही दिशा, बेहतर प्रशिक्षण और मजबूत सरकारी सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकती हैं।

छत्तीसगढ़ ने झारखंड को हराकर महिला फुटबॉल में जीता गोल्ड

खेलो इंडिया और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मजबूत उपस्थिति

राज्य की खेल अकादमियों और प्रशिक्षण केंद्रों से तैयार हुए खिलाड़ियों ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। खेलो इंडिया जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में प्रदेश के खिलाड़ियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आदिवासी अंचलों से आने वाले युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह सफलता राज्य सरकार की खेल नीति और दीर्घकालिक योजनाओं की प्रभावशीलता को दर्शाती है।

डिजिटल व्यवस्था से बढ़ी पारदर्शिता

खेल प्रशासन में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। खिलाड़ियों के प्रमाण-पत्रों और उपलब्धियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे सत्यापन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को खेल विज्ञान, पोषण और एंटी-डोपिंग संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को सुरक्षित और पेशेवर वातावरण प्राप्त हो रहा है।

विश्वस्तरीय खेल अधोसंरचना गढ़ता छत्तीसगढ़

नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी खेल नीति का उत्कृष्ट उदाहरण है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेडियम राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर नई पहचान दिला रहा है। यहां आयोजित बड़े टूर्नामेंटों ने प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, जबकि युवाओं को विश्वस्तरीय खेल वातावरण उपलब्ध कराकर छत्तीसगढ़ को उभरते खेल केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

खेल अकादमियां

बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर सहित अनेक स्थानों पर आधुनिक खेल अकादमियां संचालित खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं।

बस्तर ओलंपिक

दूरस्थ वनांचल के हजारों युवाओं को मिला मंच, नक्सल हिंसा से प्रभावित एवं आत्मसमर्पित युवाओं की सहभागिता से सामाजिक समरसता को मिली नई मजबूती।

राष्ट्रीय उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया, नई ऊंचाईयों को छुआ।

युवा सशक्तीकरण

युवा महोत्सव, नेतृत्व विकास, सामाजिक जागरुकता और फिटनेस कार्यक्रमों से हजारों युवाओं को सकारात्मक दिशा और नई पहचान।

RO- 48382/5

“ खेलों की ताकत से आगे बढ़ता छत्तीसगढ़ — अवसर, सम्मान और उपलब्धियों का नया अध्याय ”

खेल एवं युवा कल्याण विभाग

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950